आज का विचार

बिना बताये वो हर बात जान लेती है, मां तो मां होती है, मुस्कुराहटों में भी गम पहचान लेती है।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

पंचकूला । रविवार, 5 अप्रैल, 2026 वर्ष 1, अंक 232, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: HRHIN/25/A2164 Established 2025 www.citydarpan.com

हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत की कूटनीतिक सफलता, अभी तक कुल आठ जहाज सुरक्षित निकले, और दो जहाज निकलने की तैयारी में

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

पश्चिम दिशा में जारी जंग के दौरान भारत के एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने सफलता पूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर आज एक बार फिर देश को काफी राहत वाली खबर दी है। अमेरिका और इजरायल तथा ईरान के बीच जारी जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते गुजरने वाले माल वाहक जहाज और ऑयल या गैस टैंकर की आवाजाही लगभग ठप पड़ी हुई है। ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी कर देने के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा मंडराने लगा है। ऐसी स्थिति में भारत के ऑयल और गैस टैंकर्स के इस रास्ते से सुरक्षित गुजरने से भारत की कूटनीतिक सफलता जग जाहिर हो गई है।

हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के कारण वहां दुनिया भर के जहाज फंसे हुए हैं। वहीं भारत एक-एक कर अपने जहाजों को वहां से सुरक्षित निकल रहा है। ग्रीन सानवी समेत अभी तक कम से कम आठ भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकल चुके हैं। इनमें ग्रीन सानवी के अलावा शिवालिक, नंदा देवी, जग लाड़की, पाइन गैस, जग वसंत, बीडब्ल्यू टायर और बीडब्ल्यू एल्म के नाम शामिल हैं।

इन आठ जहाजों के अलावा दो और जहाज ग्रीन आशा और जग विक्रम के भी आने वाले दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचने की उम्मीद है। इस तरह भारत का नाम उन देशों में शामिल हो गया है, जिनके सबसे ज्यादा जहाज युद्ध प्रभावित हॉर्मुज

स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरे हैं। इससे भारत की ऊर्जा सप्लाई बनी हुई है और आम लोगों की ईंधन की जरूरत पूरी हो रही है।

जानकारों का कहना है कि इन जहाजों के सुरक्षित गुजरने से यह साफ है कि भारत ने मुश्किल हालात में भी अपनी ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखा है। भारत के आठ जहाजों के सुरक्षित निकल जाने के बावजूद इस समय 15 से ज्यादा भारतीय झंडे वाले जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर मौजूद हैं, जिन पर करीब 485 भारतीय नाविक सवार हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार ईरान से बातचीत कर जल्दी ही इन जहाजों को भी हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित निकालने में सफल रहेगी।

आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट समुद्र का वह संकरा रास्ता है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 30 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है। युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद ईरान ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया था। हॉर्मुज का रास्ता सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसके एक तरफ ओमान है और दूसरी तरफ ईरान। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं, जो किसी भी विशाल टैंकर को यहां अपने हमले से कुछ देर में ही समुद्र में डुबो सकती हैं।

राहत की बात ये है कि युद्ध के बावजूद ईरान के साथ भारत सरकार लगातार कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखे हुए है। इसी बातचीत के कारण पिछले सप्ताह ही ईरान ने कहा था कि अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी देशों के अलावा मित्र देशों के जहाज ईरानी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में हॉर्मुज को पार कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट उन देशों के लिए चालू है, जो तेहरान के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्हें दोस्त माना जाता है। इस क्रम में उन्होंने भारत का उल्लेख भी दोस्त के रूप में किया था।

केरल में डबल इंजन सरकार से विकास को मिलेगी रफ्तारः नरेन्द्र मोदी

एजेंसी (हि.स.)
तिरुवल्ला

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को केरल के तिरुवल्ला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने पर विकास कार्यों में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में केरल की जनता ह्लऐतिहासिक बदलावह्व के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरूआत केरल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को नमन करते हुए की। उन्होंने श्री वल्लभम मंदिर, संत तिरुवल्लुवर, सबरीमाला और स्वामी अयप्पा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार चुनावी माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है और लोगों में राजग के प्रति समर्थन स्पष्ट दिख रहा है।

मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों और गोवा में, जहां ईसाई आबादी भी महत्वपूर्ण संख्या में है, राजग सरकारों ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछले 50-60 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, वह राजग सरकारों ने करके दिखाया है। उन्होंने दावा किया कि केरल में भी राजग सरकार बनने पर राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और किसानों व मछुआरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राज्य की वामपंथी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबरीमाला रेल परियोजना में अनावश्यक देरी की गई है, जिससे तिरुवल्ला और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को नुकसान हुआ है। यह परियोजना न केवल श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ह्लडबल इंजनह्व सरकार बनने पर इस परियोजना से जुड़ी सभी अड़चनें दूर कर दी जाएंगी।

राज्य के बुनियादी ढांचे की स्थिति पर चिंता जताते हुए मोदी ने कहा कि सड़कों, पुलों और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने लंबे समय तक इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, जिससे लोगों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में केरल को पहले की तुलना में पांच गुना अधिक धनराशि दी है, लेकिन उसका अपेक्षित लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं का रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन है। उन्होंने कहा कि राज्य को उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप और कौशल विकास पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि केरल को आगे बढ़ने के लिए भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक राजनीति जैसी बाधाओं को हटाना होगा।

महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि राजग सरकार की नीतियों का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिला है। सरकार ने शौचालय निर्माण, जनधन खातों की सुविधा, महिलाओं के नाम पर घर, मुद्रा योजना के तहत ऋण और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने जैसे कई कदम उठाए हैं। लखपति दीदी योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक करोड़ों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की।

विदेश नीति और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वहां की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है और हर भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके कुछ नेताओं के बयान ऐसे समय में गैर-जिम्मेदाराना हैं, जब पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति है और लाखों भारतीय वहां काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य क्षेत्रों में फंसे भारतीय मछुआरों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं। हमारे लिए उनके जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि वे सकुशल लौटें। राजनीतिक विरोधियों पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही विकास के मुद्दे पर विफल रहे हैं और अब जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों गठबंधन एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे राज्य के विकास में बाधा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित मुद्दों का भी जिक्र किया और कहा कि यदि राजग सरकार बनती है तो इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को न्याय मिलना चाहिए और आस्था के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने केरल की जनता से राजग को समर्थन देने की अपील की और विश्वास जताया कि राज्य में जल्द ही नई सरकार बनेगी, जो विकास, सुशासन और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित करेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालभैरव व बाबा विश्वनाथ की चौखट पर टेका मत्था

एजेंसी (हि.स.)
वाराणसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के अन्तिम दिन शनिवार को काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। दोनों मंदिरों में विधि विधान से दर्शन पूजन कर मुख्यमंत्री ने देश-प्रदेश में लोक कल्याण और सुख शान्ति की कामना की। मुख्यमंत्री के दौरे की शुरूआत बाबा काल भैरव के दर्शन से हुई। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने पूरी श्रद्धा के साथ काल भैरव के विग्रह की प्रदक्षिणा और आरती मंत्रोंच्चार के बीच की। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर परिसर में मौजूद बच्चों को देख मुख्यमंत्री ने उनसे आत्मीयता से बातचीत कर उन्हें दुलार भी किया।

इसके बाद वे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री को देखकर श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं का अभिवादन करते रहे। इसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में बाबा के पावन ज्योर्तिलिंग का जलाभिषेक कर षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया। इस दौरान मंदिर

परिसर 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गुंजायमान रहा।

मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री 'स्कूल चलो अभियान' की शुरूआत करेंगे। इसका जीवंत प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पांच निपुण बच्चे, पांच निपुण विद्यालय व पांच नव प्रवेशी बच्चों को सम्मानित करेंगे। यहां वे बच्चों की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे इसके बाद बच्चों से संवाद करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक प्रबंध किया गया है।

सेक्टर 37 स्थित भाजपा कार्यालय पर ग्रेनेड हमले का मामला सुलझा
पांच आरोपी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और गोला-बारूद बरामद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने संयुक्त अभियान में चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले को सफलतापूर्वक सुलझाते हुए घटना में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा एक हैंड ग्रेनेड और अन्य गोला-बारूद बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलविंदर लाल उर्फ शामी, जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, रुबल चौहान और मनदीप उर्फ अभिजोत शर्मा के रूप में हुई है। हमले में शामिल दो मुख्य

- **मॉड्यूल पाक-आईएसआई समर्थित; पुर्तगाल और जर्मनी से संचालित विदेशी हैंडलर्स की पहचान**
- **चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी**

आरोपी, गुरतेज सिंह और अमनप्रीत सिंह, वर्तमान में फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह मॉड्यूल पाक-आईएसआई द्वारा समर्थित था और पुर्तगाल व जर्मनी में स्थित विदेशी हैंडलर्स के निर्देश पर संचालित हो रहा था। आरोपी एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसमें हमले को अंजाम देने के लिए कई स्तरों पर कटआउट्स और सब-मॉड्यूल शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने हैंड ग्रेनेड, हथियार और जिंदा कारतूस से भरी खेप का परिवहन किया। इस खेप को अंतिम आरोपियों तक पहुंचाने से पहले कई ऑपरेटिव्स के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। पुर्तगाल स्थित हैंडलर बलजोत सिंह उर्फ जोट के निर्देश पर आरोपियों ने हमले की आपूर्ति और क्रियान्वयन का समन्वय किया।

जांच के दौरान संयुक्त पुलिस टीमों ने एक जिंदा हैंड ग्रेनेड और एक जिगाना .30 बोर पिस्तौल के साथ 10 जिंदा .30 बोर कारतूस बरामद किए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके, आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाया जा सके तथा मॉड्यूल के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक स्थापित किए जा सकें।

पंजाब और चंडीगढ़ में घरेलू एलपीजी सिलेंडर और फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पंजाब और चंडीगढ़ भर के जनता को आश्वस्त करना चाहती हैं कि एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और तेल कंपनियों के पास वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के लिए पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से, तेल कंपनियां 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरों की व्यवस्था कर रही है जो उपभोक्ता नियमित घरेलू एलपीजी कनेक्शन के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के अपनी दैनिक खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफटीएल सिलेंडरों का विकल्प प्रदान किया जा रहा है।

तेल कंपनियों ने पंजाब राज्य और चंडीगढ़ में अपने सभी वितरकों को निर्देशित किया है कि वे एफटीएल सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें, पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल संचालन बनाए रखें, और पात्र उपभोक्ताओं के लिए त्वरित और सुगम पहुंच सुनिश्चित करें।

उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे घबराहट में खरीदारी करने से बचें, क्योंकि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और पुनः आपूर्ति जारी है।

एलपीजी उपभोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे एलपीजी सिलेंडर केवल डिजिटल माध्यमों से बुक करें और सिलेंडर की प्राप्ति पर डीएसी (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) के माध्यम से पुष्टि करें। इससे एक सुचारु, पारदर्शी और परेशानी मुक्त डिलीवरी प्रक्रिया सुनिश्चित होगी, जिससे वास्तविक उपभोक्ताओं को समय पर सेवा मिल सकेगी। जनता का सहयोग पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सुचारु और कुशल वितरण सुनिश्चित करने में बहुत सहायक होगा।

बिहार में ही गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन का उद्देश्य पाया : उपराष्ट्रपति

एजेंसी (हि.स.)
मोतिहारी

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों, शिक्षकों और विद्वानों को संबोधित करते हुए बिहार की ऐतिहासिक और वैचारिक विरासत की सराहना की।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह भूमि महान विचारों की धरती है, जहां गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जैसी महान हस्तियों ने ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन का उद्देश्य तय किया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म और समाजवादी विचारधारा ने आकार लिया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने देश की नैतिक और राजनीतिक चेतना को नई दिशा दी। साथ ही उन्होंने अपने युवावस्था के दिनों को याद करते हुए 1974 की क्रांति में अपनी भागीदारी का भी जिक्र किया।

सीपी राधाकृष्णन ने कहा, बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे दूरदर्शी नेता दिए हैं, जिन्होंने भारत की नैतिक और राजनीतिक चेतना को आकार दिया। मैं खुद, जब 18 या 19 साल का था, तो कोयंबटूर के जिला महासचिव के तौर पर 1974 की क्रांति का हिस्सा बना।

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने असाधारण विकास किया है। छात्रों से उन्होंने राष्ट्रवाद को अपनाने और एक स्वस्थ, मजबूत तथा नैतिक समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आान किया, जो किसी भी अनैतिक चीज को स्वीकार न करे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में हो रहे नवाचारों को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों के योगदान की भी सराहना की।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। कार्यक्रम के बाद वे पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड स्थित भितिहरवा गांधी आश्रम का दौरा कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) जनरल सैयद अता हसनैन, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कृषि क्षेत्र का गेमचेंजर साबित होगा रायसेन का तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेलाः शिवराज

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाला उन्नत कृषि महोत्सव 2026: प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण खेती का गेमचेंजर राष्ट्रीय कृषि मेला होगा, जो तीन दिनों में किसानों के जीवन में नई उम्मीद, नई तकनीक और नए बाजार अवसर लेकर आएगा। शनिवार को जारी की गई जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह ने आज केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायसेन में मेला स्थल दशहरा मैदान का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और महोत्सव के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजन स्थल दशहरा मैदान को तीन बड़े हैंगर और तीन सेमिनार हॉल के रूप में विकसित किया गया है। हैंगर-1 में कृषि एरीना, फॉर्म मशीनरी, एग्री इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, सॉइल न्यूट्रीशन, सीड वर्ल्ड, किसान सेवाएँ और इनोवेशन एंड रिसर्च झ्रकंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य संस्थान के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। इसी तरह, हैंगर-2 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सिंचाई कंपनियाँ, मृदा पोषण, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशनझ्र राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशनझ्र राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशनझ्र राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, मार्केटिंग-किसान उत्पादक संगठन और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए स्टॉल निर्धारित हैं।

हिमाचल प्रदेश में बारिश, बर्फबारी-ओलावृष्टि से कंपकंपी, एक हफ्ते तक खराब मौसम का अलर्ट

बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी

10 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने का अनुमान

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में सर्दी लौट आई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफानी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले एक हफ्ते तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

कई जिलों में आज भी खराब मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 10 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में लाहौल-स्पीति के गोंधला में 13 सेंटीमीटर और केलांग-हंसा में करीब 7.5 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। अटल टनल और आसपास के इलाकों में सुबह से हल्की बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के चलते फिलहाल सोलंग नाला से आगे फोर बाई फोर वाहनों को ही जाने की प्रशासन ने अनुमति दी है। इसके अलावा सराहन, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर, बिलासपुर, कल्पा, मनाली, स्लैपर और भुंतर समेत कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। मंडी जिला में ओलावृष्टि भी है, जबकि हमीरपुर, सुंदरनगर और अन्य इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। लाहौल स्पीति के ताबो में आज न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री, शिमला में 9.4 डिग्री, मनाली में 7.2 डिग्री, सुंदरनगर में 13.2 डिग्री, भुंतर में 11.1 डिग्री, कल्पा में 3.2 डिग्री, ऊना में 15.0 डिग्री, नाहन में 13.1 डिग्री, पालमपुर में 12.0 डिग्री, सोलन में 12.0 डिग्री,

कांगड़ा में 15.3 डिग्री, मंडी में 14.1 डिग्री और बिलासपुर में 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट के कारण शिमला और मनाली सहित कई स्थानों पर लोगों ने फिर से गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि आज किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का ओरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर और मंडी सहित कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग के पूवार्नुमान के अनुसार आज गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। 5 और 6 अप्रैल को भी अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। 7 और 8 अप्रैल को फिर से तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है, जबकि 9 अप्रैल को भी कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ मौसम खराब रह सकता है। बीती रात हुई बारिश और बर्फबारी के बाद आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं।

अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन बल्कि इससे बढ़ जाते हैं आपदा जोखिम : उपायुक्त

एनओसी के बिजली, पानी एवं सीवरेज कनेक्शन न देने तथा उल्लंघन की स्थिति पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए

एजेंसी (हि.स.)

धर्मशाला

उपायुक्त कांगड़ा हेम राज बैरवा ने कहा कि अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे भविष्य में बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े जोखिम भी बढ़ जाते हैं।

इसलिए सभी विभागों को सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने यह बात शनिवार को डीआरडीए सभागार, धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में जिला कांगड़ा के विभिन्न योजना एवं विशेष क्षेत्रों में हो रहे अनाधिकृत निर्माण तथा अवैध प्लाटिंग की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि जिन मामलों में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 16-सी तथा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 लागू होते हैं, उनमें नगर एवं ग्राम योजना विभाग की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री न की जाए, ताकि सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया जा सके। बैठक में अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 83-एक के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।

इसके तहत बिना एनओसी के बिजली, पानी एवं सीवरेज कनेक्शन न देने तथा उल्लंघन की स्थिति पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि विकास कार्य पूरी तरह नियमानुसार एवं योजनाबद्ध तरीके से किए जाएं, ताकि जिला कांगड़ा में संतुलित एवं व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके। इससे पूर्व बैठक में मंडलीय नगर योजनाकार, धर्मशाला रसिक शर्मा ने जिला कांगड़ा के अंतर्गत आने वाले योजना क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों तथा फारेन व डीम्ड योजना क्षेत्रों के बारे में तथा उनमें लागू हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जिला कांगड़ा में हो रही अवैध प्लाटिंगध/कालोनियों तथा अनाधिकृत निर्माण के मामलों से भी सभा को अवगत करवाया।

शिमला में समर सीजन से पहले ही उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, होटलों में 60% ऑक्यूपेंसी

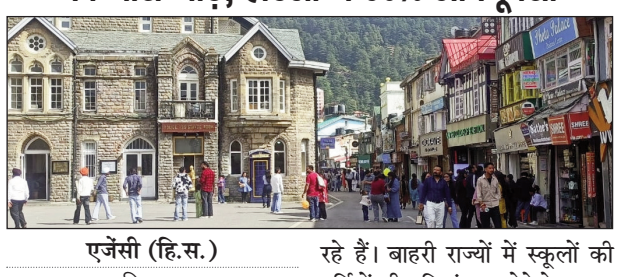

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

पहाड़ों की रानी शिमला में इस वीकेंड सैलानियों की आमद में साफ बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश के मैदानी इलाकों में बढ़ रही तपिश के बीच यहां के ठंडे सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। समर पर्यटन सीजन आधिकारिक रूप से 15 अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही शहर के पर्यटन कारोबार में रौनक लौटने लगी है।

इस वीकेंड के दौरान रिज मैदान और मालरोड पर सैलानियों की चहल-पहल देखी जा रही है। परिवारों के साथ घूमने आए पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। बाहरी राज्यों में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने के कारण भी लोगों ने शिमला का रुख करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा विदेशी सैलानियों के समूह भी इन दिनों शिमला पहुंच रहे हैं। होटल कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार इस वीकेंड पर शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी पहले के मुकाबले बेहतर रही है। शिमला होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने शनिवार को बताया कि इस वीकेंड शिमला के होटलों में कमरों की ऑक्यूपेंसी करीब 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो पिछले दिनों की तुलना में अधिक है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

एचपीटीडीसी होटलों के निजीकरण पर भाजपा ने प्रदेश सरकार को घेरा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में एचपीटीडीसी (हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम) के होटलों को निजी हाथों में दिए जाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सहजल और प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस मामले में सरकार के भीतर तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। डॉ. राजीव सहजल और संदीपनी भारदाज ने शनिवार को एक बयान में कहा कि एक ओर एचपीटीडीसी के अध्यक्ष आरएस बाली की ओर से यह कहा जा रहा है कि उन्हें होटलों के निजीकरण की जानकारी नहीं है, जबकि दूसरी ओर सरकार की ओर से इन्हें निजी हाथों में देने की प्रक्रिया की बात सामने आ रही है। उन्होंने इसे सरकार की कन्फ्यूजन की स्थिति बताया और कहा कि इससे लोगों के बीच गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एचपीटीडीसी के होटल प्रदेश के पर्यटन ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, और इन्हें घाटे का कारण बताकर निजी हाथों में देना प्रदेश की संपत्तियों को कमजोर करने जैसा कदम है। उनके अनुसार, एक तरफ इन होटलों के निर्माण और मरम्मत पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें निजी क्षेत्र को देने की तैयारी सवाल खड़े करती है।

सप्ताह में दो दिन आम लोगों के लिए खुलेगा लोकभवन, राज्यपाल की घोषणा

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

शिमला स्थित लोकभवन अब सप्ताह में दो दिन आम लोगों के लिए खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने यह घोषणा शनिवार को लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। इस अवसर पर राजस्थान, ओडिशा और बिहार का स्थापना दिवस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्साह के साथ मनाया गया।

राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन केवल सरकारी गतिविधियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि आम लोगों की भागीदारी और जुड़ाव का भी केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सप्ताह में दो दिन लोक भवन को आम नागरिकों के लिए खोलने का उद्देश्य यह है कि प्रदेश के लोग इस महत्वपूर्ण संस्थान को नजदीक से देख सकें और इसके साथ अपना संबंध महसूस करें। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में एकता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी पहलें अलग-अलग राज्यों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को समझने का अवसर देती हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान, ओडिशा और बिहार जैसे राज्य अपनी प्राचीन सभ्यता, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए देशभर में जाने जाते हैं। इन राज्यों के लोगों ने हिमाचल प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल राजस्थान, ओडिशा और बिहार से जुड़े सरकारी कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश में रहने और काम करने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उन्हें अपनापन और सहयोग का वातावरण मिला, जो राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने अतिथियों को हिमाचली परंपरा के अनुसार टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक एकता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया।

संक्षिप्त-समाचार

शिमला में गलत पार्किंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस से कहासुनी, महिला ने मांगी लिखित माफी

शिमला। राजधानी शिमला में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी होती दिखाई दे रही है। यह घटना शुक्रवार की है। इस मामले में शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वीडियो में दिख रही घटना गलत तरीके से खड़ी गाड़ी के कारण हुई थी। इससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ। इस घटना के बाद महिला ने लिखित में ट्रैफिक पुलिस कर्मी से माफी मांगी है। पुलिस के अनुसार एक महिला और एक पुरुष अस्थायी नंबर वाली गाड़ी से बालूगंज की ओर जा रहे थे। घोड़ा अस्पताल के पास वाहन को सड़क पर ही खड़ा कर दिया गया। इस दौरान पुरुष आजीविका भवन से बर्गर लेने चला गया, जबकि महिला गाड़ी में ही बैठी रही। वाहन सड़क पर इस तरह खड़ा होने से ट्रैफिक बाधित हो रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने महिला से गाड़ी हटाने और सही जगह पर खड़ी करने को कहा। इस बात को लेकर महिला और पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस का कहना है कि इस दौरान महिला का व्यवहार कुछ समय के लिए उग्र हो गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि बाद में महिला ने अपने व्यवहार के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी से लिखित रूप में माफी मांगी

पेड़ से लटका मिला महिला का शव आत्महत्या की आशंका

शिमला। जिला शिमला के चिडगांव थाना अंतर्गत खशाधार गांव में एक महिला का शव पेड़ से लटका मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस की शुरूआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी है। पुलिस को यह सूचना शुक्रवार शाम को रॉबिन पुत्र कहान चंद निवासी खशाधार गांव की ओर से दी गई। उन्होंने बताया कि उनके बगीचे में काम करने वाले नेपाली मूल के चौकीदार की पत्नी रेखा ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बागीचे में एक पेड़ से महिला का शव लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर मौके पर जांच की। प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान महिला के शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए, केवल गर्दन पर फंदे के निशान मिले। मौके से कोई सुसाइड नोट या संदिग्ध वस्तु भी बरामद नहीं हुई है। महिला के पति राम राज ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह सुबह काम पर गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं मिली। तलाश करने पर बाद में वह बागीचे में पेड़ से लटकी हुई मिली। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पतालभेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो पाएगी।

गांदरबल मुठभेड़ को लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को गांदरबल मुठभेड़ को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायकों ने हाल ही में हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग उठाई और इसे गंभीर मामला बताया। दरअसल, 31 मार्च को अरहामा के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सेना ने एक व्यक्ति को मार गिराने का दावा किया था, जिसकी पहचान गांदरबल निवासी राशिद अहमद मुगल के रूप में हुई। सेना का कहना है कि वह एक आतंकवादी था, लेकिन मृतक के परिवार ने इस दावे को खारिज करते हुए मुठभेड़ को फर्जी बताया है। परिवार का आरोप है कि राशिद का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने शव को अंतिम संस्कार के लिए वापस करने की मांग की है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। शनिवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को छोड़कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकांश विधायकों ने इस घटना की निंदा की और अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ विधायक मुबारक गुल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यदि किसी निर्दोष की हत्या हुई है तो यह बेहद गंभीर मामला है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय विधेयक-2026 पारित, उच्च शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को सदन ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन से संबंधित जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 (विधायी प्रस्ताव संख्या 08/2026) को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक शिक्षा मंत्री सकीना इटू द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संचालन और निगमन के साथ-साथ उनके प्रबंधन और शैक्षणिक मानकों को विनियमित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके और छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके। विधेयक पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि सरकार ने इसे तैयार करने से पहले उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी पहलुओं और चिंताओं पर व्यापक विचार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कानून जम्मू-कश्मीर में उच्च शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक के लागू होने से उन छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा, जो अब तक उच्च शिक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने को मजबूर थे।

आईआईटी द्वारा माइंड ट्री स्कूल का एग्रीमेंट रद्द करने पर तनातनी, मामला हाई कोर्ट पहुंचा

एजेंसी (हि.स.)

मंडी

आईआईटी कैंपस में चल रहे माइंड ट्री स्कूल का एग्रीमेंट रद्द करने का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। स्कूल के छात्रों के भविष्य को लेकर माइंड ट्री स्कूल प्रबंधन ने मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया है। माइंड ट्री शिक्षण संस्थान के संचालक हृदेयश मदान का कहना है कि माइंड ट्री स्कूल वर्ष 2017 से आईआईटी मंडी के सालगी कैंपस में चल रहा है। उसी साल आईआईटी मंडी ने समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर एक अच्छे शिक्षण संस्थान से सीबीएससई से जुड़ा स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे थे।

उन्होंने बताया कि सभी औपचारिक्ताओं व मंजुरियों के बाद, आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अनुमति से स्कूल शुरू हुआ और 33 साल की बिल्डिंग लीज पर समझौता हुआ। लेकिन साजिश के तहत संस्थान को आर्थक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई और अंत में 33 साल की बिल्डिंग लीज को एक झटके में रद्द कर दिया गया। जिससे स्कूल में पढ़ रहे नौंवीं से जमा दो कक्षाओं के छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2022 तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन वर्ष 2022 में नई स्कूल मैनेजिंग कमेटी एसएमसी बनने के बाद समस्याएं शुरू हुईं है। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार एसएमसी की भूमिका सलाह देने की होती है, लेकिन आईआईटी मंडी के कुछ सदस्यों ने रोजमर्रा के कामों में दखल देना शुरू कर दिया। उन्होंने हम पर ऐसे फैसले मानने का दबाव डाला, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता था। हमने शिक्षा के स्तर से समझौता करने से मना कर दिया। इसके बाद बदले की भावना से ग्रसित होकर माइंड ट्री सकूल प्रबंधन के समक्ष आर्थिक परेशानियां खड़ी की गई। खाली जगहों पर भी किराया छह गुणा तक बढ़ा दिया गया, गलत तरीके से जीएसटी की मांग की गई जो ट्रस्ट पर लागू नहीं होता, और कई बेवजह के मुद्दे उठाए गए।

राजौरी में वाहन छोड़ने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में पुलिस हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

राजौरी। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को राजौरी जिले के थानामंडी पुलिस स्टेशन के एक हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान थानामंडी पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद इलियास के रूप में हुई है। यह कार्रवाई रियासी निवासी अब्दुल हामिद की शिकायत के बाद की गई जिन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त वाहन को छोड़ने के बदले पैसे मांग रहा था। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने पहले ही 5,000 रुपये दे दिए थे लेकिन उस पर अतिरिक्त 10,000 रुपये देने का दबाव डाला जा रहा था जिसके कारण उसने एसीबी से संपर्क किया। शिकायत के अनुसार दुर्घटना तब हुई जब अब्दुल हामिद शाहदरा शरीफ जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने पहले ही 5,000 रुपये दे दिए थे। अब जांच अधिकारी 10,000 रुपये और मांग रहा था। मुझे बताया गया कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वे मामले को लंबा खींचेंगे और मेरा वाहन नहीं छोड़ा जाएगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे बहुत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य : केवल सिंह पठानिया

एजेंसी (हि.स.)

धर्मशाला

विधानसभा उपमुख्य सचेतक एवं विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। जिससे लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। यह उद्गार उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बटबला में जल शक्ति विभाग के तहत उठाऊ पेयजल योजना मनेई-परगोड के संवर्धन के अंतर्गत लगभग 3.29 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना का भूमिपूजन करने के उपरांत व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में 4 जल भंडारण टैंक भी बनाए जाएंगे। इससे पूर्व उन्होंने लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से निमार्णाधीन उठाऊ पेयजल योजना मनेई-परगोड के चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। यह परियोजना एडीबी के अंतर्गत है, जिसके तहत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 20 जल भंडारण टैंक बनाए जाएंगे। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लोगों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्लांट का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र इसका लाभ मिल सके इसके उपरांत उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष समस्याओं के शीघ्र निपटारे हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े।

एसपी बृजेश शर्मा को भावभीनी विदाई, कार्यकाल की सराहना में आयोजित सम्मान समारोह

एजेंसी (हि.स.)

जम्मू

जिला ग्रामीण एसपी बृजेश शर्मा के स्थानांतरण के अवसर पर श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा एक भावभीनी विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेकर उनके कार्यकाल की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में बृजेश शर्मा ने कहा कि जिले में कार्य करना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा। उन्होंने पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इसमें उन्हें स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने ट्रस्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां के लोगों का स्नेह वह हमेशा याद रखेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री ने कहा कि बृजेश शर्मा ने अपने कार्यकाल में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता का परिचय दिया तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर तहसीलदार भलवाल मोनिका शर्मा और एडीपीओ दोमाना मुदस्सर ने भी उनके प्रशासनिक समन्वय और नेतृत्व की सराहना की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में सभी ने मिलकर एसपी बृजेश शर्मा को सम्मानित किया और उनके आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

खौफ की बरसी **आज भी खतरे की जद में हिमाचल**

121 साल पहले कांगड़ा भूकंप से 20 हजार मौतें

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

अब 'जोन-6' की नई चेतावनी

4 अप्रैल 1905 का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी दर्दनाक तारीख के रूप में दर्ज है, जिसे आज भी याद करते ही लोगों के मन में दहशत की तस्वीरें उभर आती हैं। आज ही के दिन कांगड़ा क्षेत्र में 7.8 से 7.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। इसने पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को हिला कर रख दिया था। इस भूकंप में 20 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई थी और करीब एक लाख से ज्यादा भवन पूरी तरह जमींदोज हो गए थे।

कांगड़ा, धर्मशाला और मैक्लोडगंज जैसे शहरों की अधिकांश इमारतें मलबे में बदल गई थीं। इतिहासकारों के अनुसार यह भूकंप पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का अब तक का सबसे घातक भूकंप माना जाता है। उस समय 53 हजार से अधिक मवेशियों की भी मौत हुई थी और जलसेतु तथा जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह ठप हो गई थीं। उस दौर में इस आपदा से उबरने की लागत करीब 2.9 मिलियन रुपये आंकी गई थी, जो आज के हिसाब से बहुत बड़ी राशि मानी जाती है। इसी त्रासदी की याद में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आज 4 अप्रैल को 'आपदा जागरूकता दिवस' के रूप में मना रहा है। हर साल इस दिन राज्यभर में स्कूलों, संस्थानों और समुदाय स्तर पर भूकंप से बचाव की तैयारियों को लेकर अभ्यास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे भविष्य में ऐसी किसी बड़ी आपदा से नुकसान कम किया जा सके। हालांकि, 121 साल बाद भी हिमाचल प्रदेश भूकंप के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिसंबर 2025 में जारी नए

भूकंपीय जोन मानचित्र के अनुसार पूरे हिमाचल प्रदेश को अब भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील 'जोन-6' यानी सुपर-क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि प्रदेश का हर जिला बड़े भूकंप के खतरे वाले क्षेत्र में आता है और यहां मजबूत तैयारी की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अध्ययन के अनुसार यदि हिमाचल प्रदेश में आधी रात के समय 8.0 तीव्रता का भूकंप आता है तो करीब 1 लाख 60 हजार लोगों की मौत और लगभग 11 लाख लोगों के घायल होने की आशंका जताई गई है। यह अनुमान बताता है कि राज्य में भूकंप से बचाव की तैयारी कितनी जरूरी है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। वर्ष 2023 में राज्य में 11 हजार से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। वर्ष 2025 में भी करीब 7,500 मकानों को नुकसान पहुंचा और कई जगहों पर भूमि धंसने की घटनाएं सामने आईं। विशेषज्ञों के अनुसार कमजोर निर्माण गुणवत्ता, ढलानों पर अनियोजित निर्माण और जल निकासी की खराब व्यवस्था इसके प्रमुख कारण हैं। पारंपरिक 'धज्जी दीवार' और 'काठ-कुहनी' जैसी तकनीकों को छोड़कर बिना तकनीकी निगरानी के आधुनिक निर्माण भी कई क्षेत्रों में जोखिम बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि अब सुरक्षित और भूकंपरोधी निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में बीती रात महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटकों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक बार फिर 1905 की त्रासदी की याद दिला दी।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

न्योन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा, स्व. गीता शर्मा

संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा मुद्रक प्रवीन तोमर की इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22 और 49, ग्राउंड फ्लोर, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, पंचकूला-134115 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 180 ए, सेक्टर 19 सी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचकूला, हरियाणा-134113 से प्रकाशित।

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय पंचकूला होगा।

स्थानीय कार्यालय
180 ए, सेक्टर 19 सी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचकूला, हरियाणा-134113

संपर्क: 7888450261
Email: citydarpanharyana@gmail.com

विकसित फरीदाबाद रैली में मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात, 120 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास

इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सीवरेज को मजबूती, फरीदाबाद के विकास को मिली नई दिशा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को फरीदाबाद में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साढ़े 11 वर्षों में फरीदाबाद में इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, उद्योग, स्मार्ट सिटी, मेट्रो विस्तार और डिजिटल सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने शहर के समग्र विकास को नई गति देते हुए 120 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से चार महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें रेस्ट हाउस के निर्माण पर 50 करोड़ 61 लाख रुपये, डिस्पेंसरी-सह-सीएमओ कार्यालय के निर्माण पर 41 करोड़ 70 लाख रुपये, विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य पर 25 करोड़ रुपये तथा ओल्ड फरीदाबाद में स्कूल भवन निर्माण पर 3 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार फरीदाबाद को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉमिक का अनावरण किया तथा नगरवासियों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र में पिछले साढ़े 11 वर्षों में 44 सीएम घोषणाएं की गईं, जिनमें से 24 पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष पर तेजी से कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है। इसी का प्रमाण है कि संकल्प पत्र के 217 में से 60 वादे डेढ़ वर्ष में पूरे कर दिए गए हैं और बाकी पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ह्यविकसित भारत 2047ह्ल के संकल्प को हरियाणा ह्यविकसित हरियाणाह्ल के माध्यम से साकार कर रहा है। डबल इंजन सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को धरातल पर उतारा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार विकास और जनहित की बात करती है, तो विपक्ष के कुछ नेताओं को यह रास नहीं आता और वे केवल भ्रम फैलाने तथा झूठे वादों की राजनीति करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर जनता को राहत देने के निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेता वैश्विक परिस्थितियों के समय भी सस्ती राजनीति कर जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है तथा प्रदेश के 4,032 पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराकर अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, फसलों की एमएसपी पर खरीद, फसल मुआवजा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत-चिरायु योजना, मुफ्त डायलिसिस तथा बिना पर्ची-खर्ची सरकारी नौकरियां जैसी योजनाओं से हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 में भी किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और गरीबों के लिए अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। इनमें हरियाणा एग्री डिस्कॉम, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, 3 लाख लखपति दीदी, 4 हजार नए राशन डिपो, अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नए प्लॉट आवंटन जैसे निर्णय शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित फरीदाबाद केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक व्यापक विजन है, जिसमें हर नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उच्च जीवन स्तर उपलब्ध होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि फरीदाबाद का विकास किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा और सरकार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद को इंटरनेशनल ग्लोबल कॉरिडोर बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट तक की दूरी मात्र 30 मिनट में तय की जा सकेगी, जिसमें वर्तमान में लगभग दो घंटे लगते हैं। आरटीएस (रीजनल ट्रांजिट सिस्टम) के माध्यम से फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा के बीच दूरी कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद को बाढ़ मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद अब हरियाणा की नई अंतरराष्ट्रीय सिटी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित एफएमडीए की बैठक में फरीदाबाद के विकास कार्यों के लिए 985 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण सौगात दी गई, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने फरीदाबाद के विकास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली, राज्य मंत्री श्री राजेश नागर, श्री गौरव गौतम, विधायक श्री मूलचंद शर्मा, श्री सतीश फागना, श्री धनेश अदलखा, श्री हरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री की फरीदाबाद को बड़ी सौगात, जंक्शन सुधार से लेकर मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल तक कई घोषणाएं

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को फरीदाबाद में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली के दौरान फरीदाबाद के लिए कई महत्वपूर्ण विकास घोषणाएं करते हुए कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के प्रमुख जंक्शनों का चरणबद्ध सुधार किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक सुचारु हो और प्रदूषण में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि भूजल आधारित जलापूर्ति के कारण गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों को देखते हुए अपर गंगा नहर से ताजा पेयजल उपलब्ध कराने की संभावना तलाशी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित कर फरीदाबाद तक गंगा नहर का पानी पहुंचाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फरीदाबाद शहर के 50 कम्युनिटी सेंटरों और पार्कों में प्रथम चरण में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी भवनों में भी संबंधित विभागों द्वारा वर्षा जल संचयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ जलभराव की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद में दिव्य नगर योजना के तहत लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से एक नेचर पार्क विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि कन्वेंशन हॉल के सामने तथा लेबर कोर्ट के निकट एचएसवीपी की लगभग 3 एकड़ भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग के ऊपर एक बड़ा बैंक्वेट हॉल विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी, जिससे क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने सेक्टर-8 में पीपीपी मोड पर मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की घोषणा भी की। साथ ही आईएमटी सेक्टर-66 को वाणिज्यिक सेक्टर के रूप में विकसित करते हुए एंटरटेनमेंट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सिनेमा हॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स से संबंधित आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी।

इसके अतिरिक्त, सेक्टर-12 स्थित स्विमिंग पूल को पीपीपी मोड पर अपग्रेड कर ऑल वेदर और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। श्री नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि हाल ही में स्वीकृत दिल्ली-गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा आरआरटीएस/नमो भारत कॉरिडोर से फरीदाबाद को आर्थिक रूप से नई मजबूती मिलेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा।

खातीवास –खेड़ी गांवों से मेरा पारिवारिक रिश्ता : स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने गांव खातीवास में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ग्रामीण विकास के लिए कटिबद्ध है। प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। खेड़ी व खातीवास गांव उनके अपने गांव हैं दोनों गांवों से उनका पारिवारिक रिश्ता है, जब भी मदद की जरूरत पड़ी, यहां के लोगों ने दिल खोलकर मदद की है, दोनों गांवों के विकास के मामले में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने खातीवास व खेड़ी गांवों के विकास के लिए दस-दस लाख रुपए देने की घोषणा की।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव शनिवार को झज्जर के गांव खातीवास में आयोजित अभिनंदन समारोह में ग्रामीण सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि खेड़ी खातीवास गांवों के ग्रामीणों ने जो मान सम्मान दिया है वे कभी नहीं भूल पाएंगी। चूंकि इन गांवों से मेरा वर्षों पुराना पारिवारिक जुड़ाव भी है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत खेड़ी व खातीवास की तरफ से जो मांग पत्र मिला है, उनमें अधिकांश मांगों को पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी निकासी के लिए जो पाइप लाइन का काम है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। क्षेत्र के लोग किसी भी जनहित के कार्यों को लेकर उनसे कभी भी मिल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में सरकार की तरफ से एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि मशीनें और एक्सपर्ट स्टाफ लगाया गया है। आयुष्मान योजना के तहत भी लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकार सभी क्षेत्रों और वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को बेहतर इलाज, दवाइयों की उपलब्धता और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका आमजन को पूरा लाभ मिल रहा है।

सांसद नवीन जिन्दल की पहल पर वीर नारियों व पूर्व अवार्डी सैनिकों को वितरित किए गए सम्मान राशि के चैक

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

भारत रणभूमि दर्शन कार्यक्रम के दौरान सांसद नवीन जिन्दल द्वारा कही गई बात को पूरा करते हुए शनिवार को सैनिक विश्राम गृह कुरुक्षेत्र में वीर नारियों और पूर्व अवार्डी सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 20 वीर नारियों तथा 7 पूर्व अवार्डी सैनिकों को 21-21 हजार रुपये की सम्मान राशि के चैक वितरित किए गये। इस बारे में जानकारी देते हुए सांसद कार्यालय प्रभारी एवं पूर्व आईएएस अधिकारी धर्मवीर सिंह ने कहा कि सैनिकों का त्याग और बलिदान राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। वीर नारियां और हमारे सैनिक केवल सम्मान के पात्र ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है।

जिला कुरुक्षेत्र से सम्मानित होने वाली वीर नारियों में हरभजन कौर, सुरजीत कौर, कृष्णा देवी, सुखविंदर कौर, दलजीत कौर, ममता शर्मा, दलजीत कौर, पार्वती देवी, धन्नी देवी, प्रेरणा, पुष्पा देवी, गुरमीत कौर, सतपाल कौर सत्या देवी, सुनीता देवी, सिमरनजीत कौर, सुरक्षा देवी, सुंदरी देवी, गुरजीत कौर और उषा रानी उपस्थित रहीं जबकि पूर्व अवार्डी सैनिकों में कैप्टन रावेल सिंह, सूबेदार भजन सिंह, कर्नल कुलवंत सिंह, हवलदार जसबीर सिंह, नायब सूबेदार श्रवण सिंह, सिपाही बलकार सिंह और हवलदार सुरेंद्र सिंह ने सम्मान राशि के चैक प्राप्त किए।

उल्लेखनीय है कि सांसद नवीन जिन्दल ने हाल ही में आयोजित ह्यभारत रणभूमि दर्शनह्ल कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों और पूर्व अवार्डी सैनिकों को सम्मान राशि के रूप में 21-21 हजार रुपये देने की बात कही थी, जिसे आज साकार करते हुए इस सम्मान राशि के चैक वितरित किए गये।

गलत कृषि नीतियों से किसान, व्यापारी और मजदूर सभी परेशानः कुमारी सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/करनाल

सिरसा की सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस कांग्रेस की महासचिव कुमारी सैलजा आज करनाल जिले की घरौंडा अनाज मंडी के दौरे पर पहुंचीं। उन्होंने फसल खरीद का जायजा लिया और किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों से बातचीत की। कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर छोटे व्यापारियों और आढ़तियों को कमजोर करने में लगी हुई है तथा किसानों पर तरह-तरह के नियम लागू कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर किसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी नीतियां उसकी समस्याओं को और बढ़ा रही हैं। उन्होंने मंडियों में पोर्टल व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पोर्टल का खुलना अच्छी बात है, लेकिन उसका सही ढंग से काम करना अधिक जरूरी है। जब तक सरकार जमीनी स्तर पर किसानों, मजदूरों और आढ़तियों की समस्याओं को नहीं समझेगी, तब तक स्थिति में सुधार संभव नहीं है। कुमारी सैलजा ने कहा कि हर सीजन में किसानों को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। फसल तैयार होने के बाद किसान खरीद का इंतजार करता है, लेकिन बारिश या ओलावृष्टि से फसल खराब हो जाती है। इसके बाद मुआवजे के लिए उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आता है और बारिश हो जाती है, तो उसकी फसल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। लंबी कतारों में खड़े किसानों की फसल समय पर नहीं बिक पाती, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इससे पूर्व सैलजा ने सिरसा और फतेहाबाद जिलों का दौरा कर वहां भी किसानों और व्यापारियों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याओं को सुना था। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोलते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह आम जनता को राहत दे। उन्होंने कहा कि एलपीजी की बढ़ती कीमतें लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है।

संक्षिप्त-समाचार

फसल खरीद सुनिश्चित करना और समय पर भुगतान करवाना सरकार की प्राथमिकता: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा

चंडीगढ़। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा फसल खरीद को लेकर मंडियों में लागू की गई नई व्यवस्थाएं पूरी तरह से किसानों के हित में हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य स्थानीय किसानों की फसल की पहले खरीद सुनिश्चित करना और उन्हें समय पर भुगतान दिलाना है, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। कैबिनेट मंत्री शनिवार को हिसार की अनाज मंडी में फसल खरीद कार्यों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंडी में अधिकारियों, किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। साथ ही उनकी कई प्रकार की शंकाओं का भी निवारण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि मंडियों में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू की गई हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। मंत्री रणबीर गंगवा ने खरीद एजेंसियों और मंडी प्रशासन के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से ढिलाई बरती जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि खरीद प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। सरकार के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा भी प्रत्येक मंडी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं।

सम्मान

राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 112 विद्यार्थियों को अलग-अलग विषयों में पीएच.डी. की दी डिग्री

विकसित भारत के विकास में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका: प्रो. असीम कुमार घोष

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

हरियाणा के राज्यपाल और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पीएच.डी, यूजी, पीजी की डिग्री हासिल करने के बाद अब युवा पीढ़ी अपने अगले लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगी। यह युवा पीढ़ी नवाचार, उद्यमिता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करके भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी। इस देश की युवा पीढ़ी को विकसित राष्ट्र को एक राष्ट्रीय मिशन समझकर आगे बढ़ना होगा। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष शनिवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 35वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के अनुमोदन पर सर्वोच्च न्यायालय, भारत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर ऑफ लॉ में मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में अलग-अलग विषयों में पीएच.डी के 112 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान दी और 89 विद्यार्थियों को अपनी-अपनी कक्षाओं में टॉप करने पर गोल्ड मेडल और प्रमाण देकर सम्मानित किया। इस दीक्षांत समारोह में पीएच.डी सहित पीजी और यूजी के करीब 3000 विद्यार्थियों को डिग्री देकर सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी, न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज, न्यायाधीश न्यायमूर्ति अलका सरीन को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने विद्यार्थियों से नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। आज का दीक्षांत समारोह केवल शिक्षा की यात्रा का समापन नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरूआत है। राज्यपाल ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत 2047 का लक्ष्य एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसके वास्तविक शिल्पकार देश के युवा हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पारंपरिक नौकरी तक सीमित न रहने और नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बनने की प्रेरणा दी। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को डॉक्टर ऑफ लॉ (मानद) उपाधि प्रदान किए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान उनके विधि और न्याय क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की पहचान है। उन्होंने इसे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय बताया कि न्यायमूर्ति बिंदल इसी संस्थान के पूर्व छात्र भी हैं। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्वविद्यालय को नैक से ए$$ ग्रेड प्राप्त हुआ है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्लैटिनम अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने शोध, पेटेंट, नए शैक्षणिक कार्यक्रमों और इंडस्ट्री 4.0 से जुड़े आधुनिक विषयों में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि भगवद्गीता के उस संदेश की याद दिलाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ-साथ मूल्यों को भी जीवन में अपनाने की अपील की।

सर्वोच्च न्यायालय, भारत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि यदि राष्ट्र सशक्त होगा, तो हम सभी स्वतः सशक्त होंगे। यदि हम केवल अपनी व्यक्तिगत प्रगति के बारे में सोचेंगे, तो हम अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, वह इसी राष्ट्र की देन है। इसलिए राष्ट्र के प्रति योगदान देना हमारा पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है।

इस अवसर पर राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष, डॉ. ममता सचदेवा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां की कुलपति प्रो. सुदेश छिक्कारा, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. करतार सिंह धीमान, कुलसचिव प्रो. वीरेन्द्र पाल, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. राकेश कुमार, डीन ऑफ कॉलेजिज प्रो. ब्रजेश साहनी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. ए.आर. चौधरी, परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंकेश्वर प्रकाश, प्रो. संजीव अग्रवाल, प्रो. प्रीति जैन, प्राक्टर प्रो. अनिल गुप्ता, प्रो. संजीव शर्मा, प्रो. सुनील ढींगरा, प्रो. भगवान सिंह चौधरी, प्रो. डी.एस. राणा, प्रो. आरके. मोदगिल, प्रो. रीटा, प्रो. परमेश कुमार, प्रो कुसुमलता, डॉ. जितेन्द्र खटकड़, लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया, उप-निदेशक डॉ. जिम्मी शर्मा सहित विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी सदस्य, कोर्ट के सदस्य, डीन, निदेशक, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के अवसर पर सामूहिक फोटो की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष व हरियाणा राज्य की प्रथम महिला मित्रा घोष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व उनकी धर्मपत्नी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी, न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज, न्यायाधीश न्यायमूर्ति अलका सरीन, कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा सहित विभिन्न संकायों के डीन, निदेशक, विभागाध्यक्ष, शिक्षकों का समूह फोटोग्राफ लिया गया जो सभी के यादगार बना।

संपादकीय

हॉर्मुज में भारत का बढ़ता दबदबा: दुनिया के टॉप देशों में शामिल, ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा संकेत!

वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हाल के संकेत बताते हैं कि इस रणनीतिक मार्ग से गुजरने वाले जहाजों में भारतीय जहाजों की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है और भारत इस मार्ग का उपयोग करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो गया है। यह प्रवृत्ति न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक जरूरतों का संकेत देती है, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार में उसकी मजबूत होती स्थिति को भी उजागर करती है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य भौगोलिक दृष्टि से छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत तेल आयात के जरिए पूरा करता है, के लिए इस जलडमरूमध्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण ने ऊर्जा की मांग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खपत में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके चलते भारत को खाड़ी देशों–जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात–से बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। इन आयातों का अधिकांश हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते भारत तक पहुंचता है, जिससे इस मार्ग पर भारतीय जहाजों की आवाजाही स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। भारतीय शिपिंग कंपनियों और तेल कंपनियों ने भी अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। अब वे अधिक कुशल और बड़े जहाजों का उपयोग कर रही हैं, ताकि परिवहन लागत कम हो और आपूर्ति श्रृंखला अधिक विश्वसनीय बन सके। इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहल के तहत देश में जहाज निर्माण और समुद्री अवसंरचना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे भारत की समुद्री क्षमताओं में सुधार हुआ है और वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हुआ है। हालांकि, हॉर्मुज जलडमरूमध्य की संवेदनशीलता हमेशा चिंता का विषय बनी रहती है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष और समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरे इस मार्ग को अस्थिर बना सकते हैं। अतीत में कई बार इस क्षेत्र में टैंकरों पर हमले और जहाजों की जब्ती जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क रहे। इस दिशा में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना की तैनाती को मजबूत किया गया है और समुद्री निगरानी बढ़ाई गई है। 'मिशन सागर' और 'ऑपरेशन संकल्प' जैसे अभियानों के माध्यम से भारत ने न केवल अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान दिया है। इसके अलावा, भारत ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाकर समुद्री सुरक्षा को लेकर साझा प्रयासों को भी मजबूत किया है। भारत की विदेश नीति में भी इस क्षेत्र को लेकर संतुलन देखने को मिलता है। एक ओर भारत ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को बनाए रखता है, वहीं दूसरी ओर वह अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत साझेदारी बनाए हुए है। यह संतुलन भारत को इस संवेदनशील क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने में मदद करता है। ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भारत वैकल्पिक उपायों पर भी काम कर रहा है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश और अन्य समुद्री मार्गों की तलाश–ये सभी कदम भविष्य के संभावित संकटों से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर जैसे परियोजनाएं भी भारत को वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान कर सकती हैं। भारतीय जहाजों की बढ़ती उपस्थिति का एक और महत्वपूर्ण पहलू 'ब्लू इकॉनमी' से जुड़ा है। भारत समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स सुधार और डिजिटल तकनीकों का उपयोग–ये सभी पहल भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की समुद्री भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। यदि वर्तमान रुझान जारी रहता है, तो भारत न केवल ऊर्जा आयातक के रूप में, बल्कि एक प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में भी उभर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि देश अपनी समुद्री नीतियों को और अधिक सुदृढ़ करे, निवेश को बढ़ाए और तकनीकी नवाचारों को अपनाए। अंततः, हॉर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों की बढ़ती मौजूदगी एक व्यापक परिवर्तन का संकेत है। यह न केवल भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को दशार्ता है, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका को भी उजागर करता है। हालांकि, इस मार्ग से जुड़े जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक संतुलित और दूरदर्शी नीति के माध्यम से भारत इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।

देश में गिरता शिक्षा का स्तर

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(हि.स)

अभी मेडिकल पीजी में शून्य (0) पर्सेंटाइल पर प्रवेश का मुद्दा पुराना भी नहीं हुआ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम ने देश की शिक्षा के हालातों के पोल खोलकर ही रख दी है। शिक्षा के मंदिर में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेक्चरर के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में राजनीति विज्ञान के लेक्चरर के पद के लिए हजारों युवाओं ने परीक्षा दी और 225 पद होने के बावजूद केवल छह परीक्षार्थी चयन के योग्य पाये गये। मजे की बात है कि परीक्षा देने वाले हजारों युवाओं में मात्र 219 युवा भी न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक भी प्राप्त नहीं कर पाए। हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि फिजिकल एजुकेशन के 37 पदों के लिए एक भी नहीं और होम साइंस जैसे विषय के लेक्चरर के पद के लिए केवल एक परीक्षार्थी ही सफल हो सका। अब एक ओर देश में प्रतिपक्ष बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से उठा रहा है तो तो दूसरी और भर्ती वाले पदों के लिए न्यूनतम अहर्ता अंक प्राप्त करने में भी आज के युवा सफल नहीं हो पा रहे हैं।

यह कोई राजस्थान की ही बात नहीं है अपितु यह समूचे देश की शिक्षा के स्तर की बानगी है। क्योंकि निश्चित रुप से राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अन्य प्रदेशों के युवा भी परीक्षार्थी रहे होंगे। बेरोजगारी की समस्या अपनी जगह पर है पर दूसरी ओर स्नातक, स्नातकोत्तर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के ज्ञान के स्तर को इससे आंका जा सकता है। यही कारण है कि आज मल्टी टास्क सर्विस जिसे परंपरागत शब्दों में कहा जाए तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद या शहरी निकायों में सफाई कर्मचारी के कुछ पदों के लिए ही हजारों लाखों युवा आवेदन करने लगे हैं और तस्वीर का एक पहलू यह है कि इन युवाओं में उच्च और तकनीकी शिक्षा यहां तक की इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए तक आवेदन कर रहे हैं।

यह हमारे शैक्षणिक संस्थानों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान के स्कूल लेक्चरर के लिए परीक्षा देने वाले युवाओं ने निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान की उच्च पढ़ाई की होगी। उनका न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक भी प्राप्त नहीं करना चिंताजनक है। वैसे देखा जाए तो 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर चयनित होने वाले स्कूल लेक्चरर से आप बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अपेक्षा करेंगे तो बेमानी होगी। हालात वास्तव में गंभीर है और यही कारण है कि नौकरी के लिए आयोजित परीक्षाओं में नकल, गलत प्रयोग और पेपर आउट व डमी कैंडिडेट द्वारा परीक्षाएं देने के लिए माफिया की बन पड़ी है।

मेडिकल पीजी में जीरो पर्सेंटाइल पर प्रवेश के निर्णय पर यह अवश्य संतोष की बात है कि फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के इस निर्णय की खिलाफत करने की हिम्मत दिखाई है। इसमें कोई दोराय नहीं कि देश में शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा कर सबके लिए शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकी। अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटी सहित यूनिवर्सिटी नित नई खुलती जा रही है। इसे अच्छा भी माना जा सकता है पर सौ टके का सवाल यह है कि क्या शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने के माध्यम ही बन कर रह गए हैं। राजनीति विज्ञान तो उदाहरण मात्र है, सवाल यह है कि परीक्षा देने वाले हजारों प्रतियोगियों ने किसी एक संस्थान से तो डिग्री प्राप्त की नहीं होगी। यह सोचने का वक्त है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं।

शिक्षण संस्थानों की स्तरीयता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह से कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों की बाढ़ आई हुई है उसके परिणाम भी इन परिणामों में कहीं दूर-दूर तक लक्षित नहीं हो रहे। सरकार और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को कम से कम अपने स्तर का तो ध्यान रखना ही होगा। शिक्षा की गुणवत्ता और तकनीकी अध्ययन की वैश्विक पहचान बनाना सरकार और अध्ययन केन्द्रों की पहली और अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए, पर यहां तो स्थानीय स्तर पर ही खरे नहीं उतर पा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जीरो पर्सेंटाइल वालों को विशेषज्ञ बनाकर इलाज का लाइसेंस देंगे तो इसे आम नागरिकों की जिंदगी से खिलवाड़ और शिक्षा पद्धति के साथ मजाक बनाना ही है। सरकार और आयोग को समय रहते शिक्षा के स्तर को बनाए रखने की पहल करनी होगी। इसी से देश की शिक्षा की गुणवत्ता देश दुनिया में बनी रह सकेगी। सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं को खासतौर से आगे आना होगा।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि दिनभर काम की अधिकता आपको व्यस्त रख सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी यात्रा के संकेत भी मिल रहे हैं। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: करियर को लेकर मन में असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है। आमदनी बढ़ेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। घर के बड़े सदस्य आपकी सराहना करेंगे। दोस्तों से सलाह लेना फायदेमंद साबित होगा। छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। अपने शौक पूरे करने के लिए खर्च कर सकते हैं। खानपान में सावधानी रखें, खासकर मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं। आलोचनाओं से मन आहत हो सकता है। प्रेम संबंधों में अत्यधिक निर्भरता से बचें। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: व्यापार में अच्छी आमदनी के संकेत हैं, लेकिन सरकारी कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। परिवार के प्रति व्यवहार संतुलित रखें, क्योंकि कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। मन में अनिश्चित भय बना रह सकता है। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। विपरीत लिंग के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे, लेकिन स्वार्थी रवैये से बचना जरूरी है। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: आज आपका स्वभाव थोड़ा संदेहपूर्ण रह सकता है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। घरेलू विवाद तनाव का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से जरूरी काम छूट सकते हैं। हालांकि आप पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

तुला: आपके व्यवहार और व्यक्तित्व की प्रशंसा होगी। गले से जुड़ी समस्याएं या सर्दी-जुकाम हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त रह सकती है। रुके हुए कार्यों को पूरा करने का दबाव रहेगा। सोशल मीडिया पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। विदेश से जुड़ी नौकरी करने वालों की आय में वृद्धि हो सकती है। परिवार में सम्मान मिलेगा, लेकिन कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

धनु: जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। गुस्सैल लोगों से दूरी बनाकर रखें। आय के नए स्रोत बनने से खुशी मिलेगी। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। *(सिटी दर्पण)*

मकर: वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ने की संभावना है। मन को स्थिर रखने की जरूरत है। फिल्म या मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़े अवसर मिल सकते हैं। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: व्यापार में आज अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जिनमें आपकी रुचि नहीं है। लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। *(सिटी दर्पण)*

मीन: आज नया काम शुरू करने से बचें। व्यवसाय में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। पुरानी बीमारी फिर से परेशान कर सकती है, इसलिए सतर्क रहें। बच्चों को लेकर चिंता हो सकती है। अपने काम में बाहरी हस्तक्षेप से बचना बेहतर रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

भय से विश्वास तक: एक युगांतकारी परिवर्तन

बृजमोहन अग्रवाल (हि.स)

छह दशकों तक भारत की आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास यात्रा को चुनौती देता रहा नक्सलवाद आज अपने निर्णायक अवसान की अवस्था में पहुँच चुका है। यह केवल एक सुरक्षा सफलता नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय संकल्प की विजय है, जिसमें स्पष्ट नीति, अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति और केंद्र-राज्य के अभूतपूर्व समन्वय ने मिलकर एक जटिल और दीर्घकालिक समस्या का समाधान किया है। नक्सलवाद का यह अवसान इस सत्य को पुनः स्थापित करता है कि भारत में बंदूक की शक्ति अंततः लोकतंत्र की सामूहिक शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया- इसके पीछे दशकों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान और एक ऐसी रणनीतिक निरंतरता रही है, जिसने अंततः इस चुनौती को निर्णायक रूप से परास्त किया।

नक्सलबाड़ी से रेड कॉरिडोर तक: एक वैचारिक आंदोलन का हिंसक विस्तार

भारत में नक्सलवाद का उदय वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुआ, जिसकी वैचारिक जड़ें तत्कालीन सोवियत संघ और चीन की उग्र वामपंथी विचारधारा में थीं। अपनी विकास विरोधी छवि के कारण जब बंगाल में इस विचारधारा के प्रति विरोध पनपने लगा तो अपने विस्तार के लिए नक्सलवाद ने 'सॉफ्ट टारगेट्स' की तलाश शुरू की- ऐसे क्षेत्र जहाँ शासन की पहुँच सीमित हो, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ अधिक हों और जनजागरूकता कम हो। देश के वनांचल, आदिवासी और खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र इस दृष्टि से सबसे आसान लक्ष्य थे। नक्सलवाद विस्तार की इसी रणनीति के तहत तथाकथित 'रेड कॉरिडोर' विकसित हुआ, जो तिरुपति से पशुपति तक फैले विशाल भूभाग में फैल गया।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से घिरा छत्तीसगढ़, जिसका लगभग 42 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, इस रेड कॉरिडोर का रणनीतिक केंद्र बन गया। पड़ोसी राज्यों से अपनी गतिविधियाँ सीमित रखने का अघोषित समझौता कर नक्सली अबूझमाड़ क्षेत्र में संगठित होते चले गए। अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण दशकों तक प्रशासनिक सर्वेक्षण से दूर रहा अबूझमाड़ नक्सलियों का सुरक्षित शेल्टर बन गया।

विचारधारा से विचलन: माओवाद से मनीवाद तक

समय के साथ नक्सलवाद ने अपनी मूल वैचारिक पहचान खो दी और एक हिंसक आर्थिक उगाही तंत्र में परिवर्तित हो गया। बस्तर और सरगुजा जैसे वनाच्छादित जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलियों ने समानांतर सत्ता संरचना स्थापित कर दी, जहाँ तथाकथित 'जन अदालतों' के माध्यम से भय आधारित नियंत्रण कायम किया गया।

छत्तीसगढ़ के खनिज सम्पन्न क्षेत्रों की खदानें, विद्युत परियोजनाएँ, तेंदूपत्ता व्यापार- सभी उनके लिए उगाही के स्रोत बन गए। सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों, ठेकेदारों और यहाँ तक कि पुलिस बलों से भी जबरन वसूली की जाने लगी। यह उगाही धीरे-धीरे इतनी बढ़ी कि छत्तीसगढ़ में इसका वार्षिक आंकड़ा हजारों करोड़ रुपये तक पहुँचने की चर्चा होने लगी।

सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में यह विचारधारा समाप्त हो गई। चीन ने भी माओवाद की सशस्त्र संरचना को छोड़कर आर्थिक सुधारों पर आधारित पूंजीवादी कम्युनिज्म मॉडल को अपना लिया, लेकिन भारत में नक्सलवाद अपने मूल उद्देश्यों से भटककर लेवी वसूली और हिंसा फैलाने का टूल बन गया। नक्सलवाद के झंडाबरदारों ने विचारधारा को त्यागकर इसे अपने आर्थिक हितों की पूर्ति और आतंक फैलाने का साधन बना लिया।

नक्सलवाद के वैचारिक समर्थन की राजनीतिक पृष्ठभूमि

दुर्भाग्य से, कांग्रेस नीत सरकारों के लंबे शासनकाल में नक्सलवाद के प्रति स्पष्ट और कठोर नीति का अभाव रहा क्योंकि उस दौर में केंद्र और कई राज्यों में भी वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के सहयोगी की भूमिका में थीं। सत्ता के लिए वामपंथ के साथ कांग्रेस की राजनीतिक निकटता का परिणाम यह हुआ कि नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार करने की बजाय इसे सामाजिक-आर्थिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कर वैधता प्रदान करने की नीति हावी हो गई। उस दौर में प्रशासनिक तंत्र के भीतर भी यह वैचारिक भ्रम दिखाई देता था। नक्सलवाद को सामाजिक समता पाने का वर्ग संघर्ष ठहराने के दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किए गए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नीतियाँ भी नक्सलवाद के विरुद्ध कठोर होने के बजाय सहानुभूतिपूर्ण हो गई थीं। इस ढुलमुल नीति का परिणाम यह हुआ कि नक्सलवाद देश के 12 राज्यों के लगभग 180 जिलों में फैल गया और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से ही प्रदेश के समग्र विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया।

राष्ट्रीय चेतना का उदय: मेरे प्रारंभिक अनुभव छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहते हुए मुझे बस्तर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला जहां नक्सलवाद रूपी दैत्य से मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ और यह आभास भी हुआ कि दंडकारण्य में इस दैत्य का दमन केवल हथियारों से नहीं किया जा सकता। नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष की भूमि तैयार करने के लिए इस क्षेत्र में वैचारिक जनजागरण की नितांत आवश्यकता थी और इसलिए जनजातीय समाज के बीच राष्ट्रीयता का अलख जगाने के प्रकल्प में मैंने भी अपनी भागीदारी निभाई।

1990 के दशक में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में रायपुर के पुराने कमिश्नर कार्यालय के बीटीआई कम्युनिटी परिसर में आयोजित बैठक में पहली बार यह निर्णय लिया गया कि नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष को राष्ट्रीयता के व्यापक संदर्भ में लड़ा जाएगा। यही वह निर्णायक मोड़ था जब नक्सलवाद की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के परिप्रेक्ष्य में देखा गया।

जब हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा की गोपनीय बैठक

वर्ष 2003 से 2006 के बीच जब मुझे मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की सरकार में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व मिला, तब प्रदेश में पहली बार नक्सलवाद के विरुद्ध एक ठोस, नीतिगत और समन्वित अभियान प्रारंभ किया गया। 'ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट कमांड और ज्वाइंट पॉलिसी' के सिद्धांत पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए गए। तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल के साथ इस विषय पर मेरी कई गंभीर और विस्तृत मंत्रणाएँ हुई थीं। उस दौर में इस विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए देश के इतिहास में पहली बार विधानसभा में गोपनीय बैठकों का आयोजन किया गया, ताकि लोग बिना किसी भय के खुलकर अपनी बात रख सकें। तात्कालीन स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली इन बैठकों से अधिकारियों और पत्रकार को भी दूर रखना जरूरी हो गया था। इन मंत्रणाओं के परिणामस्वरूप बनी रणनीति के तहत तात्कालीन डीजीपी ओपी राठौड़ के नेतृत्व में कई अभियान चलाए गए और इसी क्रम में सलवा जुडूम जैसे जनअभियान की शुरूआत हुई।

सलवा जुडूम: जनभागीदारी का ऐतिहासिक अध्याय

हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अशिक्षा, अज्ञानता और दुष्प्रचार के कारण स्थानीय समाज का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद के प्रति सहानुभूति रखता था। इस स्थिति को बदलने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया गया। स्कूलों, महाविद्यालयों और छात्रावासों में पर्चे और साहित्य वितरित किए गए। घर-घर जाकर नक्सलवाद की वास्तविकता को उजागर किया गया। इस अभियान में दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसे संस्थानों से जुड़े राष्ट्रवादी विचारकों और छात्रों का भी सहयोग लिया गया।

जनजातीय समाज को यह समझाया गया कि नक्सल नेतृत्व में स्थानीय छत्तीसगढ़ी आदिवासियों की भागीदारी शून्य है। जल, जंगल, जमीन के नारों की आड़ में हमारे भोले-भाले आदिवासियों का उपयोग केवल एक साधन के रूप में किया जा रहा था। यह भी सामने आया कि नक्सलियों के द्वारा आदिवासी युवतियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उन्हें शोषण का शिकार बनाया जाता था, उन्हें विवाह तक नहीं करने दिया जाता और सामान्य सामाजिक जीवन जीने तक से वंचित रखा जाता था। इन कड़वी सच्चाइयों के उजागर होने से आई जनजागृति का परिणाम यह हुआ कि नक्सलवाद को मिलने वाला सामाजिक समर्थन कमजोर पड़ने लगा।

जब नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा बने सलवा जुडूम के अगुआ

'सलवा जुडूम' केवल एक सरकारी पहल नहीं थी बल्कि आदिवासी समाज के भीतर से उठा एक स्वाभाविक जनआंदोलन था, जिसने पहली बार सही मायने में नक्सलवाद को चुनौती दी। तात्कालीन नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा ने न केवल इस अभियान को पुरजोर समर्थन दिया बल्कि इसे जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इस संघर्ष से जुड़े रहने के कारण अंततः उन्हें अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी- जो इस आंदोलन की गंभीरता और बलिदान की पराकाष्ठा का साक्षात प्रमाण है। नक्सलवाद ने हमें झीरम जैसे दंश दिए जिसमें प्रदेश के अग्रणी नेता काल कलवित हो गए।

सलवा जुडूम जन आंदोलन को अगर व्यापक संस्थागत समर्थन मिला होता तो निश्चित ही नक्सलवाद का उन्मूलन उसी दौर में हो जाता, पर वैधानिक संस्थानों में काम करने वाले कई लोगों की सलवा जुडूम के खिलाफ लामबंदी, अर्बन नक्सली बुद्धिजीवियों के वैचारिक विरोध और केंद्र सरकार के नीतिगत असमंजस के कारण यह अवसर पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सका।

समन्वित नेतृत्व से निर्णायक परिवर्तन

वास्तविक परिवर्तन तब आया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध स्पष्ट, कठोर और समन्वित नीति अपनाई गई। नक्सलवाद को महज कानून-व्यवस्था की समस्या न मानकर, राष्ट्र की एकता, विकास और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर चुनौती मानते हुए नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए समयबद्ध रणनीति तैयार की गई।

केंद्र और राज्य सरकारों के सशक्त समन्वय के परिणामस्वरूप दिसंबर 2023 से मार्च 2026 के बीच सुरक्षा बलों ने लगातार सटीक और प्रभावी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों कुख्यात नक्सलियों को निष्क्रिय किया, हजारों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी सुनिश्चित की। लैंड माइंस का व्यापक निष्क्रियकरण हुआ और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। केंद्र और राज्य के समन्वित दृष्टिकोण और साझे प्रयासों से छह दशक पुराने नक्सलवाद के नासूर को जड़ से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की बुनियाद पर विकसित छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अब हमें नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में गढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। जिस प्रकार आर्टिकल 370 के उन्मूलन से जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति और राष्ट्रीय एकीकरण का आधार बना, उसी प्रकार नक्सलवाद का समापन छत्तीसगढ़ के लिए एक नए युग का द्वार खोल रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी शासन की पहुँच सीमित थी, वहाँ अब सड़कों का जाल बिछ रहा है, मोबाइल नेटवर्क स्थापित हो रहे हैं, बैंकिंग सेवाएँ सुलभ हो रही हैं और शिक्षा-स्वास्थ्य की सुविधाएँ तेजी से विस्तार पा रही हैं। बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वह केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। जहाँ कभी गनतंत्र का साया था, वहाँ आज जनतंत्र विश्वास और विकास के साथ स्थापित हो रहा है।

अब चुनौती इस सफलता को स्थायी बनाने की है- ऐसी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक संरचना खड़ी करने की, जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसक विचारधारा को पनपने का अवसर न मिले। आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास, कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि वे पुनः हिंसा के रास्ते पर न लौटें।

बुलेट पर बैलेट की निर्णायक विजय

नक्सलवाद पर यह विजय केवल एक आंतरिक सुरक्षा अभियान की सफलता नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। यह उस निर्णायक परिवर्तन का संकेत है, जहाँ भय की राजनीति को विश्वास की शक्ति ने प्रतिस्थापित किया है और जहाँ बंदूक के साये में जी रहे समाज ने विकास और सहभागिता के मार्ग को अपनाया है। जो लोग बंदूक और गोलियों के दम पर भय के माध्यम से छत्तीसगढ़ में छद्म राज्य की कल्पना करते थे उनका अंत हुआ और लोकतंत्र की विजय हुई। बुलेट पर बैलेट की जीत हुई। देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और विशेषकर बस्तर की जनता को इस ऐतिहासिक विजय की हृदय से शुभकामनाएं।

(लेखक, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री एवं वर्तमान में रायपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं।)

घुमंतू समाज की पहचान का आधार बनेगी जनगणना

डॉ. सत्यवान सौरभ (हि.स)

देश में कुछ समुदाय ऐसे भी हैं, जिन्हें आज तक ठीक से गिना ही नहीं गया–न आंकड़ों में, ना नीतियों में, और ना ही संवेदनाओं में। ये वे लोग हैं, जिन्हें कभी अंग्रेजों ने "जन्मजात अपराधी" घोषित कर दिया था और आजादी के 78 साल बाद भी जिनकी पहचान उसी कलंक के बोझ तले दबी हुई है। यह विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियां हैं। यह आज भी भारत के विकास के नक्शे में अदृश्य बनी हुई हैं। ऐसे में 2027 की जनगणना केवल एक सांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऐतिहासिक न्याय का एक सुनहरा अवसर है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम इन समुदायों के जीवन पर एक अमिट दाग बनकर चिपक गया। इस कानून ने उन्हें जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया, जिससे उनके जीवन का हर पहलू संदेह और निगरानी के घेरे में आ गया। यह केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं था, बल्कि सामाजिक बहिष्कार की एक संगठित व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के बाद 1952 में इस अधिनियम को समाप्त कर इन समुदायों को 'विमुक्त' तो कर दिया गया, लेकिन समाज की मानसिकता आज भी उस औपनिवेशिक सोच से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप, ये समुदाय आज भी पुलिस के संदेह, सामाजिक तिरस्कार और सरकारी उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों को आजादी के बाद मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए था, वे आज भी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। स्थायी निवास का अभाव, लगातार प्रवास और दस्तावेजों की कमी इनके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे सामान्य दस्तावेज, जो किसी भी नागरिक के अधिकारों का आधार होते हैं, इन समुदायों के लिए एक सपना बनकर रह जाते हैं। जब पहचान ही नहीं होगी, तो अधिकार कैसे मिलेंगे? यही कारण है कि ये समुदाय सरकारी योजनाओं, आरक्षण और कल्याणकारी कार्यक्रमों से लगातार बाहर रह जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति और भी चिंताजनक है। घुमंतू जीवनशैली के कारण बच्चों की पढ़ाई लगातार बाधित होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने के कारण स्कूलों में नामांकन और निरंतरता दोनों ही मुश्किल हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, इन समुदायों में ड्रॉपआउट दर अत्यधिक है और साक्षरता का स्तर बेहद निम्न। शिक्षा से वंचित रहना केवल एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के भविष्य को अंधकार में धकेल देना है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। स्थायी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होने के कारण ये लोग कुपोषण, संक्रमण और अन्य बीमारियों से जूझते रहते हैं। सरकारी अस्पतालों तक पहुंच की कमी और जागरूकता का अभाव उनकी समस्याओं को और गंभीर बना देता है।

इन सबके बीच सबसे ज्यादा कठिनाई महिलाओं को झेलनी पड़ती है। एक ओर वे सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझती हैं, तो दूसरी ओर लैंगिक भेदभाव और असुरक्षा की मार भी सहती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहने के कारण उनकी स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। कई मामलों में वे राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी दूर रहती हैं, जिससे उनकी आवाज नीति-निर्माण तक पहुंच ही नहीं पाती। नीतिगत स्तर पर भी इन समुदायों के साथ लंबे समय तक न्याय नहीं हो पाया है। 2019 में विकास एवं कल्याण बोर्ड का गठन और सीड जैसी योजनाएं शुरू करना सकारात्मक कदम जरूर हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा है। बजट की कमी, कमजोर कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति इन योजनाओं को प्रभावी बनने से रोकती है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि इन समुदायों के बारे में सटीक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जब तक किसी समूह की वास्तविक संख्या, स्थिति और आवश्यकताओं का स्पष्ट आकलन नहीं होगा, तब तक उसके लिए प्रभावी नीतियां बनाना संभव नहीं है।

यही वह बिंदु है, जहां 2027 की जनगणना एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अगर इस जनगणना में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए अलग कॉलम और कोड शामिल किया जाता है, तो यह उनके अस्तित्व को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह पहचान, सम्मान और अधिकारों की बहाली का प्रश्न है। हालांकि, इस दिशा में कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। जाति जनगणना को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस जारी है और ऐसे में एक नई श्रेणी जोड़ना विवाद को और बढ़ा सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह मुद्दा केवल राजनीति का नहीं, बल्कि मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का है। अगर सरकार और समाज इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करें, तो इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है।

इसके लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक समन्वित रणनीति तैयार करें। स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण और डेटा संग्रह की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि घुमंतू समुदायों को सही तरीके से गिना जा सके। आधुनिक तकनीक–जैसे डिजिटल जनगणना और जीपीएस ट्रैकिंग–का उपयोग कर उनकी गतिशील जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए डेटा एकत्र किया जा सकता है। साथ ही, गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों को इस प्रक्रिया में शामिल करना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वे इन समुदायों के साथ सीधे जुड़े होते हैं और उनकी वास्तविक स्थिति को बेहतर समझते हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं बनाकर इन समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना होगा। मोबाइल स्कूल, अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र और कौशल विकास कार्यक्रम जैसे उपाय उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अलावा, पुलिस और प्रशासनिक तंत्र में संवेदनशीलता लाना भी जरूरी है, ताकि इन समुदायों के प्रति मौजूद पूर्वाग्रहों को समाप्त किया जा सके। वैश्विक स्तर पर भी ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, जहां घुमंतू और हाशिये पर मौजूद समुदायों के लिए विशेष नीतियां बनाकर उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया गया है। यूरोप में रोमा समुदाय के लिए चलाए गए कार्यक्रम इस दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण हैं। भारत भी इनसे सीख लेकर अपने संदर्भ में प्रभावी नीतियां विकसित कर सकता है।

अंततः, यह सवाल केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि उस न्याय का है, जो इन समुदायों से दशकों से छीन लिया गया है। 2027 की जनगणना इस अन्याय को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। अगर इस अवसर को भी गंवा दिया गया, तो यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं होगी, बल्कि यह हमारे संविधान के उस वादे का भी उल्लंघन होगा, जो समानता और न्याय की बात करता है। अब समय आ गया है कि हम इन अदृश्य नागरिकों को दृश्य बनाएं, उन्हें गिनें, पहचान दें और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करें, क्योंकि जब तक समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक विकास का कोई भी दावा अधूरा ही रहेगा।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

भगवंत मान सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए ओ.टी.एस. 2025 की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई की: हरपाल सिंह चीमा

अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई की गई, करदाताओं को बकाया निपटाने का आखिरी मौका

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ह्यबकाया राशि की वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटारा योजना (ओ.टी.एस.), 2025ह्ल में दो महीने के विस्तार का आधिकारिक ऐलान किया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई, 2026 कर दी गई है।पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां यह घोषणा करते हुए जोर देकर कहा कि यह विस्तार योग्य करदाताओं को अपने बकाया निपटाने और बड़ी वित्तीय राहत प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण और अंतिम अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि कर विभाग ने पहले ही टैक्स डिफॉल्टरों से संबंधित 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली है, और यदि वे इस अंतिम अवसर का तुरंत लाभ नहीं उठाते हैं तो जल्द ही इनकी नीलामी की जाएगी। यहां जारी एक प्रेस बयान के माध्यम से इस पहल की ताजा प्रगति के बारे में जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस योजना को पूरे राज्य में भरपूर और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।उन्होंने कहा, अब तक कर विभाग को सफलतापूर्वक 9,151 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस उत्साहजनक भागीदारी के चलते 134.21 करोड़ रुपये का कुल राजस्व एकत्र किया गया है, जो मौजूदा सरकार में करदाताओं के विश्वास और निरंतर राजस्व संग्रह का प्रतीक है।इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा 446.17 करोड़ रुपये की प्रभावी राहत दिए जाने से कारोबारियों को इस पहल का काफी लाभ हुआ है। पिछली ओ.टी.एस. योजनाओं की सफलता पर प्रकाश डालते हुए वित्त

मंत्री चीमा ने कहा, वित्त वर्ष 2022-23 में ओ.टी.एस.-2 के तहत 2,487 आवेदन प्राप्त हुए और उनका निपटारा किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में ओ.टी.एस.-3 के तहत लगभग 70,000 आवेदन निपटाए गए। यह ऐतिहासिक भागीदारी ऐसी योजनाओं की बड़ी क्षमता को दशार्ती है और संकेत देती है कि योग्य करदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूदा 2025 योजना के तहत लाभ लेने से वंचित है।उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय सीधे तौर पर फील्ड से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य करदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना, चल रहे मुकदमों को काफी हद तक कम करना और राज्य के खजाने के लिए राजस्व वसूली को और बढ़ाना है।

तिथि में विस्तार की सुविधा देने के बावजूद, वित्त मंत्री ने जानबूझकर डिफॉल्टर बने लोगों को सख्त और स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यह बिल्कुल अंतिम अवसर होगा। उन्होंने कहा, जो करदाता 31 मई, 2026 की अंतिम तिथि तक इस योजना में शामिल नहीं होंगे, उन्हें कानून के अनुसार सख्त वसूली कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कर विभाग ने पहले ही बड़ी संख्या में डिफॉल्ट मामलों की सक्रिय रूप से पहचान कर ली है।

वित्त मंत्री चीमा ने स्पष्ट किया कि जहां भी आवश्यक होगा, राज्य सरकार बकाया कर की वसूली के लिए संपत्तियों को जब्त करने और उनकी नीलामी की प्रक्रिया सख्ती से शुरू करेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार पुराने कर विवादों को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और अत्यंत कुशल प्रणाली प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, यह रणनीतिक पहल न केवल व्यापारिक समुदाय को उनके पुराने बकाया खत्म करने में मदद करती है, बल्कि राज्य की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाती है।सभी योग्य करदाताओं से जोरदार अपील है कि वे बढ़ाई गई अंतिम तिथि का लाभ उठाएं और भविष्य में किसी भी सख्त वसूली कार्रवाई से बचने के लिए अपने बकाया का तुरंत निपटारा करें।

दिल की बीमारियों से लेकर कैंसर तक का इलाज; आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान कर रही मुख्यमंत्री सेहत योजना

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर के साथ आपातकालीन इलाज मिल रहा, पंजाब के परिवारों पर आर्थिक बोझ घटा
- योजना राज्य के परिवारों को जानलेवा डॉक्टरी आपातकाल में समय पर इलाज मुहैया करवाने में सहायक

पंजाब की प्रमुख मुख्यमंत्री सेहत योजना स्वास्थ्य सुरक्षा की महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रही है, जो प्रति परिवार 10 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती है और अचानक डॉक्टरी आपातकाल के दौरान वित्तीय बोझ को कम करते हुए समय पर इलाज लेने में सक्षम बनाती है। कई बीमारियां जैसे दिल का दौरा, कैंसर और जन्म संबंधी जटिलताएं किसी भी समय हमला कर सकती हैं, इसलिए पंजाब सरकार का दृष्टिकोण व्यापक स्तर पर जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप के माध्यम से डॉक्टरी जरूरत और किफायती इलाज के बीच के अंतर को पूरा करने पर केंद्रित है।

दिल का दौरा, कैंसर और जन्म संबंधी जटिलताएं जैसी बीमारियां बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकती हैं, जिससे अचानक गंभीर लक्षण पैदा होते हैं और गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए तुरंत डॉक्टरी सहायता की जरूरत होती है।यह सुझाव देता है कि ऐसी स्वास्थ्य स्थितियां अक्सर गुप्त रूप से विकसित होती हैं और बिना किसी चेतावनी के हमला करती हैं, जिसके संबंध में फैसला लेने के लिए बहुत कम समय बचता है।पंजाब में इस बढ़ती चिंता को वित्तीय तैयारी के माध्यम से देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी सरकार-समर्थित पहल का उद्देश्य डॉक्टरी जरूरत और किफायती इलाज के बीच के अंतर को पूरा करना है।

पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में चल रही यह योजना हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। यह योजना सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में 2,300 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर करती है।

बड़ी और गंभीर बीमारियों की छिपी शुरूआत को उजागर करते हुए विश्व स्वास्थ्य आंकड़े समय पर फैसला लेने की जरूरत को दशार्ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दिल की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज और सांस लेने की समस्या जैसी बीमारियां हर साल विश्व भर में लगभग 75 प्रतिशत मौतों का कारण बनती हैं और बहुत से पीड़ितों को यह भी नहीं पता होता कि वे जोखिम में हैं। मोहाली के जिला अस्पताल की मेडिसिन की मेडिकल ऑफिसर डॉ. ईशा अरोड़ा ने कहा कि जब तक मरीज हमारे पास आते हैं, बीमारी अक्सर अगले चरण तक पहुंच जाती है। उन्होंने आगे कहा कि शुरूआत में ही बीमारी का पता लगाने से बेहतर नतीजों में मदद मिल सकती है, लेकिन इसे अभी भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा नियमित जांचें बहुत कम करवाई जाती हैं क्योंकि लक्षणों का पता न लगना उनमें सुरक्षित होने की गलत भावना पैदा कर देता है।

10,000 रिश्वत लेते नायब कोर्ट को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में चल रही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के दौरान लुधियाना अदालत में नायब कोर्ट के रूप में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह को 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है ।आज यहां यह जानकारी साझा करते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को चंडीगढ़ रोड, लुधियाना के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ एक केस दर्ज था और गिरफ्तारी के दौरान शिकायतकर्ता की लाइसेंसी पिस्तौल भी पुलिस ने कब्जे में ले ली थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसका लाइसेंसी पिस्तौल वापस दिलाने से संबंधित केस में मदद करने के बदले आरोपी नायब कोर्ट ने 10,000 रिश्वत और स्केचर्स जूते की

मांग की। शिकायतकर्ता ने रिश्वत और स्केचर्स जूते मांगने वाली पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता रिश्वत देने या किसी भी अन्य गैर-कानूनी तरीके का सहारा लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने विजिलेंस ब्यूरो रेंज लुधियाना से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने आरोपी नायब कोर्ट को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रिश्वत राशि और स्लेटी रंग के स्केचर्स जूते लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

पंजाब का पुलिसिंग मॉडल देशभर में नशा विरोधी मामलों में सजा दिलाने में अग्रणी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब की ह्ययुद्ध नशेयां विरुद्धह्ल मुहिम को न केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी के आधार पर बल्कि अदालतों द्वारा उन्हें सख्त सजा दिलाने में लाई जा रही तेजी के रूप में भी परिभाषित किया जा रहा है। यह नशों के खिलाफ रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए राज्य में आ रहे निर्णायक बदलाव का स्पष्ट संकेत है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार के समर्थन से इस मुहिम को लागू करने वाली एजेंसियां अब कानूनी रूप से मजबूत केस तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, ताकि तस्करों को पकड़कर उन्हें कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित किया जा सके।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों में पंजाब की 88 प्रतिशत सजा दर, जो देश में सबसे अधिक है, बेहतर और योजनाबद्ध पुलिसिंग का परिणाम है। इसमें अभियोजन-आधारित जांच, वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र करना, नशा नेटवर्क की वित्तीय ट्रैकिंग और तकनीक-आधारित खुफिया जानकारी जुटाना शामिल है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में अदालतों द्वारा निपटाए गए 4812 एनडीपीएस मामलों में से 3870 मामलों में सजा हुई, जो 80 प्रतिशत सजा दर दशार्ता है। वर्ष 2023 में 6976 मामलों में से 5635 में सजा हुई और यह आंकड़ा 81 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसी तरह वर्ष 2024 में 7281 मामलों में से 6219 में दोष तय हुये, जिससे सजा दर 85 प्रतिशत तक पहुंच गई।वर्ष 2025 में 7373 मामलों में से 6488 दोषी पाए गए, जिससे यह दर 88 प्रतिशत तक पहुंच गई।वर्ष 2026 में अब तक फैसला किये गए 1831 मामलों में से 1634 दोषियों को सजा हुई है, जिससे यह दर 89 प्रतिशत हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है।

ये परिणाम ह्ययुद्ध नशेयां विरुद्धह्ल मुहिम के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के कारण संभव हुए हैं, जिसने प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत नीतिगत दिशा और संस्थागत समर्थन प्रदान किया है।इसका मुख्य उद्देश्य नशा विरोधी प्रयासों में बरामदगी और गिरफ्तारी से आगे बढ़कर समयबद्ध सजा सुनिश्चित करना है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस सफलता का कारण पुलिसिंग के मूल तरीके में लाया गया बदलाव है। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल तस्करों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें जेल भी भेजा जाए। अब पुलिस तकनीकी और आधुनिक तरीकों से जांच करती है और उच्चतम कानूनी मानकों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार केस तैयार किया जाता है कि अदालत में मजबूत पैरवी हो सके। उन्होंने आगे कहा, नशा जब्ती से लेकर दस्तावेजीकरण और फॉरेंसिक जांच तक हर कदम पर एनडीपीएस प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाता है, ताकि कोई भी तस्कर तकनीकी खामियों के कारण सजा से बच न सके।

अधिकारियों ने बताया कि उच्च सजा दर प्रणालीगत हस्तक्षेप का स्पष्ट परिणाम है, जिसमें संरचित और योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जांच अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराना, 60-बिंदुओं वाली जांच चेकलिस्ट के साथ विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू करना और अदालतों में मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए ट्रायल स्पेशल अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है।

इस दौरान राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला के साथ एक महत्वपूर्ण संस्थागत साझेदारी भी स्थापित की गई है, जहां सभी जांच अधिकारियों के लिए छह दिन का अनिवार्य प्रमाणन प्रशिक्षण आवश्यक है। जांच की गुणवत्ता सुधारने के लिए 400 से अधिक आईओ पहले ही विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

खेतों तो प्लेट तक- पंजाब की कृषि को मजबूत करने के लिए एक नवीन पहल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब राज्य खाद्य आयोग ने ह्यआर ई : जैनरेटिंग पंजाबह्ल के सहयोग से मिट्टी से थाली तक पहल की शुरूआत की है।इस पहल का उद्देश्य पूरे राज्य में मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना और कृषि प्रणाली को मजबूत बनाना है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए, आयोग के अध्यक्ष श्री बाल मुकुंद शर्मा ने मिट्टी की घटती उर्वरता, कम होते भूजल और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ह्यआर ई : जैनरेटिंग पंजाबह्ल की संस्थापक और मुख्य संचालक सुश्री सुमित संधू (दिल्ली) को कार्यक्रम का एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करके इस सेमिनार का उद्घाटन किया।

इस सेमिनार में पंजाब, अमेरिका और ब्रिटेन के लगभग 15 विशेषज्ञों और चुनिंदा किसानों ने भाग लिया, जिन्होंने सक्रिय रूप से अपने विचार साझा किए। जैविक खेती, वैकल्पिक फसल चक्र, वर्मीकम्पोस्ट-आधारित उर्वरक, मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन, पानी का कुशल उपयोग, खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चाएँ हुईं। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के अनुरूप रहा: पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत।

प्रतिभागियों में सुमित संधू (दिल्ली), मुक्ति कुमार (जम्पल, इंग्लैंड), ज्योति सरूप (उन्नति कोऑपरेटिव), रजनीश शर्मा (वर्मीकम्पोस्ट उर्वरक विशेषज्ञ), जतिंदर कौर अरोड़ा (पूर्व कार्यकारी निदेशक, पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद), रिपनदीप सिंह (सहायक निदेशक, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, घड्डुआं), तरुण सेन (प्रबंधक, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड), एन.एस. बराड़ (अध्यक्ष, पैग्रो फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड), के.बी. सिंह (निदेशक, ढअटएळक् ढअव), जसप्रीत सिंह (हल्दी उत्पादक), चमकौर सिंह (मोगा), गुरमुख सिंह (बटाला), धालीवाल साहब (अमेरिका), सरबजीत बाजवा (अमृतसर), श्री सत्त सिंह जी, और कई अन्य प्रगतिशील किसान तथा विद्वान शामिल थे।

डॉ. रवजोत सिंह ने जेल विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की, जेल सुपरिंटेंडेंट्स के साथ की बैठक

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/होशियारपुर

पंजाब के संसदीय मामलों, एनआरआई मामलों एवं जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज होशियारपुर के जिला प्रशासनिक परिसर में सभी जेल सुपरिंटेंडेंट्स की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में श्री अरुण पाल सिंह, आईपीएस, एडीजीपी जेल, श्री सुरिंदर पाल सिंह मंड, आईपीएस, डीआईजी जेल (फिरोजपुर और पटियाला रेंज), श्री सुखमंदर सिंह मान, आईपीएस, डीआईजी जेल (अमृतसर रेंज) तथा श्री मनमोहन कुमार, डीआईजी मुख्यालय सहित सभी जेल सुपरिंटेंडेंट्स और जेल मुख्यालय के अधिकारी उपस्थित थे।

यह बैठक जेल अधिकारियों के साथ प्रारंभिक परिचय हेतु आयोजित की गई थी, जिसके दौरान जेल मंत्री को विभाग की समग्र कार्यप्रणाली और प्रमुख पहलों के बारे में अवगत कराया गया।इनमें जेलों

में भीड़भाड़ तथा उच्च जोखिम वाले कैदियों के प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटने के उपाय शामिल हैं।

जेल मंत्री को प्रस्तावित पंजाब प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल और पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स बिल के बारे में भी जानकारी दी गई, जो वर्तमान में पंजाब सरकार के विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, जिनमें राज्य की सभी जेलों में कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पदों की आवश्यकता शामिल है। कैबिनेट मंत्री ने जेल सुपरिंटेंडेंट्स द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी ध्यानपूर्वक सुना, जिनमें स्टाफ की कमी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यप्रणाली, जेलों में शौचालयों की मरम्मत और आवासीय कॉलोनियों के रखरखाव जैसी चिंताएं शामिल थीं। इस अवसर पर जेल मंत्री को चल रही और भविष्य की अवसंरचना परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जिनमें लुधियाना में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण तथा पटियाला में महिला ओपन जेल की स्थापना के प्रस्ताव शामिल हैं। जेल मंत्री ने दोनों परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया ताकि इन्हें जल्द से जल्द चालू किया जा सके।

संक्षिप्त-समाचार

चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला: पंजाब पुलिस द्वारा हैंड ग्रेनेड, जिगाना पिस्तौल सहित पांच व्यक्ति गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले में शामिल पांच आरोपियों को एक हैंड ग्रेनेड और एक .30 बोर जिगाना पिस्तौल सहित जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर इस मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान गांव माजरी (एसबीएस नगर) के बलविंदर लाल उर्फ शम्मी, गांव भरापुर (एसबीएस नगर) के जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, गांव सुजावलपुर (एसबीएस नगर) के चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, गांव ठाणा (शिमला) के रूबल चौहान और धूरी (संगरूर) के मनदीप उर्फ अभिजोत शर्मा के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल को पाकिस्तान की आई.एस.आई. का समर्थन प्राप्त था और यह पुर्तगाल तथा जर्मनी में स्थित विदेशी हैंडलरों के निदेर्शों पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपी एक संरचित नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसमें हमले को अंजाम देने के लिए कई कट-आउट और सब-मॉड्यूल शामिल थे। डीजीपी ने कहा कि हमले में शामिल दो मुख्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। इस मामले में आगे-पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए जांच जारी है। गौरतलब है कि बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-37 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर ग्रेनेड हमला हुआ था। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एआईजी स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), एसएएस नगर दीपक पारिक ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों द्वारा हैंड ग्रेनेड, हथियार और जिंदा कारतूसों की एक खेप ट्रांसपोर्ट की गई थी, जो कई गुर्गों के द्वारा होती हुयी अंतिम आरोपियों को प्राप्त हुयी थी।

अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश औलख को मानद डॉक्टरेट से नवाजा

चंडीगढ़। गोवा में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान अमेरिका की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय फ्रैंकफोर्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने भारतीय संगीत उद्योग की जानी-मानी कंपनी स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश औलख को संगीत और मनोरंजन क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑनरेरी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। यह सम्मान समारोह भारत के गोवा शहर में आयोजित किया गया, जिसमें संगीत और मनोरंजन जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि दिनेश औलख ने पंजाबी संगीत उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में स्पीड रिकॉर्ड्स ने अनेक प्रसिद्ध कलाकारों को मंच प्रदान किया और कई हिट गाने तथा एल्बम दुनिया भर में लोकप्रिय हुए। समारोह में बोलते हुए दिनेश औलख ने इस सम्मान के लिए विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरी टीम और उन कलाकारों का है जिन्होंने वर्षों से स्पीड रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी वे भारतीय संगीत और मनोरंजन उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। यह सम्मान उनके लंबे अनुभव और समर्पण की सराहना का प्रतीक माना जा रहा है।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सीएमए प्रैक्टिशनर्स कन्वेंशन-2026 का शुभारंभ

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में दो दिवसीय राष्ट्रीय कोस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स प्रैक्टिशनर्स कन्वेंशनझ्र2026 का शुभारंभ शिवालिक व्यू होटल में किया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसका उद्घाटन किया। इस कन्वेंशन में देश के विभिन्न हिस्सों से दो सौ से अधिक सीएमए उपस्थित रहे। सीएमए मनोज कुमार आनंद, चेयरमैन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने मुख्य अतिथि और प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा कन्वेंशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार अपने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और राज्य के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पंजाब ने जीएसटी कॉलेक्शन्स, एक्साइज रेवेन्यू और नॉन-टेक्स रेवेन्यू में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने यह भी बताया कि आईआईटी हैदराबाद से प्राप्त उन्नत आईटी सॉफ्टवेयर के उपयोग से सरकार ने राजस्व चोरी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के उपाय लागू करने में पंजाब देश के पहले तीन राज्यों में शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि कर चोरी की जांच के लिए आठ से दस ऐप्स पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार द्वारा शुरू किए गए ह्लस्कूल ऑफ एमिनेंसह्व जैसे प्रयासों से अनेक विद्यार्थियों ने जेईई और नीट परीक्षाएं उत्तीर्ण कर देशभर के विभिन्न पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया है।

बाबा बालक नाथ जी के जयकारो के बीच निकली भव्य शोभा यात्रा

चंडीगढ़। श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ सर्व सांझा सेवा मंडल (पंजीकृत) चंडीगढ़ की ओर से आज श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी की 23वीं विशाल शोभा यात्रा बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ निकाली गई। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिला और पूरे मार्ग में बाबा जी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। शोभा यात्रा शुरू होने से पहले श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर, सेक्टर-29 में विधिवत हवन-यज्ञ और झंडा पूजा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर बाबा जी का आशीर्वाद लिया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद शोभा यात्रा की शुरूआत की गई। यह शोभा यात्रा सेक्टर-29 स्थित मंदिर से प्रारंभ होकर सेक्टर-30,20, 21, 22, 23 के बाजारों, इसके बाद बत्रा चौक सेक्टर-37, सेक्टर-38, 40 और 41 से होती हुई अंत में श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर-42 में जाकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थानीय निवासियों, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशनों और धार्मिक संस्थाओं ने श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। जगह-जगह फूलों की वर्षा कर शोभा यात्रा का अभिनंदन किया गया।

विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले पूरे राज्य में 74 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए पंजाब पूरी तरह तैयार: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने आज बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर अभ्यास के लिए कार्यक्रम अधिसूचना जारी होने से पहले सभी प्रारंभिक गतिविधियां एक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से की जा रही हैं।

अब तक की प्रगति के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में एक व्यापक प्री-एसआईआर मैपिंग अभियान चलाया गया है।4 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 74.27 प्रतिशत मतदाताओं की विशेष गहन पुनरीक्षण रिकॉर्ड्स के साथ मैपिंग की गई है। कुल 2,14,57,521 मतदाताओं में से राज्य भर में 1,59,36,941 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है।प्री-एसआईआर अभ्यास को समय पर और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए मुख्यालय स्तर पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा प्रगति की दैनिक निगरानी की जा रही है, जिससे नजदीकी पर्यवेक्षण और समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो पाया है।जिला-वार विवरण देते हुए मित्रा ने कहा कि तरनतारन (88.64 प्रतिशत), मोगा (86.91 प्रतिशत), श्री मुक्तसर साहिब (85.47 प्रतिशत) और मानसा (84.20 प्रतिशत) जैसे जिलों में सबसे अधिक मैपिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है। लुधियाना (64.14 प्रतिशत), अमृतसर (75.60 प्रतिशत), जालंधर (68.05 प्रतिशत) और पटियाला (69.33 प्रतिशत) सहित अन्य प्रमुख जिलों में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाता 2003 की मतदाता सूचियों, जो एसआईआर प्रक्रिया के लिए एक प्रमुख संदर्भ के रूप में कार्य

करती हैं, का उपयोग करके अपने विवरण सक्रिय रूप से खोज सकते हैं और मैप कर सकते हैं। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल ँ३३स्र२://५ङ्क३ी१२ॅ्र.ङ्क५.ल्ल/ के माध्यम से 2003 की मतदाता सूची तक पहुंच सकते हैं।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि उनका नाम नहीं मिलता है, तो वे अपने परिवार के सदस्यों, जैसे माता-पिता या दादा-दादी के विवरण से मिलान करके अपने विवरण लिंक कर सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि एसआईआर अभ्यास के दौरान बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) पूरे राज्य में घर-घर जाकर गणना करेंगे।गणना फॉर्म दो प्रक्रियाओं में वितरित किए जाएंगे और सहायक दस्तावेजों के साथ एकत्र किए जाएंगे, ताकि पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक मतदाता, जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल है, के लिए इन गणना फॉर्मों को भरना अनिवार्य है।सीईओ पंजाब ने आगे कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करने और मतदाता सूचियों को सही एवं अद्यतन बनाए रखने के लिए नागरिकों का सक्रिय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा बूथ स्तर एजेंटों (बीएलए) की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 8000 से अधिक बीएलए नियुक्त किए गए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं में हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य/जिला संपर्क केंद्र पर टोल-फ्री नंबर 1950 स्थापित किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर कार्यदिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सक्रिय रहेगा। नागरिक इस नंबर के माध्यम से अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म पर ₹बुक ए कॉल विद बीएलओ₹ सुविधा का उपयोग कर-के वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मित्रा ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य सही, समावेशी और अद्यतन मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करना है, जो एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव होती हैं। उन्होंने कहा कि शैडयूल नोटिफाइड होते ही पंजाब एसआईआर अभ्यास के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने बूथ स्तर अधिकारियों के साथ सहयोग करें, ताकि घर-घर जाकर गणना शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मत 2003 की मतदाता सूची के साथ मैप किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण होना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत एक अपराध है।

ईरान ने इजराइल पर किया हवाई हमला, तीन शहरों में नुकसान

इजराइल के शहरों में मची अफरा-तफरी: बिजली गुल और इमारतें जमींदोज

एजेंसी (हि.स.)
तेल अवीव/ तेहरान

ईरान 28 फरवरी से अमेरिका-इजराइल के साथ छिड़े युद्ध में बहुत कुछ खोने के बावजूद दुश्मन को नाकों चने चबवा रहा है। राजधानी तेहरान के पश्चिम में स्थित करज में गुरुवार को महत्वपूर्ण पुल पर किए गए हमले के बाद ईरान आक्रामक हो गया है। उसने आज तड़के इजराइल के तीन शहरों पर हवाई हमला किया है। इसके अलावा अमेरिका का एक और विमान मार गिराने का दावा किया है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने रामत गान में बमबारी की है। इस बमबारी में एक इमारत ढह गई है। इसके अलावा रोश हा'यिन में किए गए हमले में बिजली गुल हो गई। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने इसकी पुष्टि की है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस का कहना है कि ईरान ने बीरशेबा के दक्षिण में स्थित नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसके अलावा बेनी ब्राक में हुए हमले में एक व्यक्ति को हल्की चोट आई आई है। उसे इलाज के लिए मयानेई हयेशुआ मेडिकल सेंटर ले जाया गया। अल जजीरा चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, करज में गुरुवार को महत्वपूर्ण पुल पर किए गए हमले के बाद ईरान ने शुक्रवार को एक अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराया। तेहरान ने आज सुबह दावा किया कि उसकी सेना ने अमेरिका के दूसरे विमान (ए-10) को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मार गिराया। इस बीच अमेरिका के ईरान में प्रमुख पुल को नष्ट करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब नागरिक सुविधाओं और बिजली संयंत्रों पर हमले झेलने के लिए तेहरान तैयार रहे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ट्रंप की धमकी को 'बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध' करने के इरादे की स्वीकारोक्ति बताया है। कुवैत ने कहा है कि ईरान ने एक जल विलवणीकरण संयंत्र और एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। तेहरान ने विलवणीकरण संयंत्र को निशाना बनाने की बात से इनकार किया है।

फोटोः हि.स.

ईरान ने एक और अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया

तेहरान/वाशिंगटन। ईरान 28 फरवरी से अमेरिका-इजराइल के साथ छिड़े युद्ध में बहुत कुछ खोने के बावजूद दुश्मन को नाकों चने चबवा रहा है। राजधानी तेहरान के पश्चिम में स्थित करज में गुरुवार को महत्वपूर्ण पुल पर किए गए हमले के बाद ईरान ने शुक्रवार को एक अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराया। तेहरान ने आज सुबह दावा किया कि उसकी सेना ने अमेरिका के दूसरे विमान (ए-10) को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मार गिराया। इस बीच अमेरिका के ईरान में प्रमुख पुल को नष्ट करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब नागरिक सुविधाओं और बिजली संयंत्रों पर हमले झेलने के लिए तेहरान तैयार रहे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ट्रंप की धमकी को 'बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध' करने के इरादे की स्वीकारोक्ति बताया है। कुवैत ने कहा है कि ईरान ने एक जल विलवणीकरण संयंत्र और एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। तेहरान ने विलवणीकरण संयंत्र को निशाना बनाने की बात से इनकार किया है। ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलें दागी हैं। 28 फरवरी से अब तक, पूरे ईरान में अमेरिकी-इजराइली हमलों में कम से कम 2,076 लोग मारे गए हैं और 26,500 घायल हुए हैं।

काठमांडू में पुलिस का रातभर चला सर्च ऑपरेशन, 195 लोग गिरफ्तार

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुलिस ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाकर बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। गुंडागर्दी, ठगी और बिचौलियागिरी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। काठमांडू के एसएसपी रमेश थापा के अनुसार, शहर के विभिन्न स्थानों से कुल 195 लोगों को पकड़ा गया। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठमेल और बुढानीलकण्ठ समेत विभिन्न क्षेत्रों से इन लोगों को हिरासत में लिया गया।

एसएसपी थापा ने बताया, 'ठमेल और विमानस्थल जैसे इलाकों में यात्रियों को खींचतान करने वाले, पहले से गुंडागर्दी में शामिल और बिचौलिया गतिविधियों में लगे 195 लोगों को नियंत्रण में लिया गया है।' पुलिस के अनुसार, इन सभी के खिलाफ आगे की जांच जारी है। वहीं, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें यात्रियों को जबरन खींचने (कस्टमर पकड़ने) के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में टैक्सी चालक और होटल प्रतिनिधि शामिल हैं।

मकवानपुर में ट्रक पलटने से त्रिभुवन राजपथ अवरुद्ध

काठमांडू। नेपाल में मकवानपुर के थाहा नगरपालिका-12 टिस्टुड स्थित त्रिभुवन राजपथ पर बीती रात लगभग डेढ़ बजे ट्रक (बा.प्र.03-001 ख 1750) पलटने से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। यह ट्रक काठमांडू से हेटौंडा की ओर जा रहा था। जिला पुलिस कार्यालय मकवानपुर के अनुसार, ट्रक आगे दाहिने हिस्से का पट्टा (मैकेनिकल हिस्सा) टूटने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक धादिंग के बेनिघाट मौवाखोला निवासी लगभग 27 वर्षीय ध्रुब घले घायल हो गए।। ट्रक से कूदने के दौरान उनके दाहिने पैर के तलवे में चोट लगी है। उन्हें इलाज के लिए पालुङ अस्पताल भेजा गया है। मकवानपुर पुलिस के प्रवक्ता डीएसपी पुष्कर बोगटी ने जानकारी दी कि सड़क खोलने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के अभी भी घटनास्थल पर ही होने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित है। सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है।

पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कटौती नया भाव 378 रुपये प्रति लीटर

एजेंसी (हि.स.)
इस्लामाबाद

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में शरीफ ने कहा कि पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। यह एक महीने तक लागू रहेगी। यह कटौती पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये प्रति लीटर की कमी के बाद की गई है।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में सरकार ने राष्ट्रीय संसाधनों से 129 अरब रुपये की सब्सिडी दी है। इन उपायों का उद्देश्य ईंधन की बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ जनता पर पड़ने से रोकना है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्षित सब्सिडी की भी घोषणा की है। मोटरसाइकिल चालकों को 100 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी।

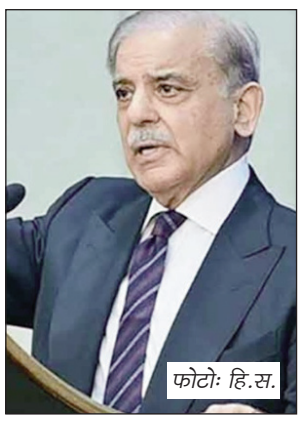
फोटोः हि.स.

परिवहन क्षेत्र को भी राहत उपायों में शामिल किया गया है। बढ़ते परिचालन खर्चों की भरपाई के लिए मालवाहक और कमर्शियल वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन बसों को हर महीने 100,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, ताकि यात्रियों के लिए किराया स्थिर रखा जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि इकोनॉमी-क्लास ट्रेन यात्रा का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा।

नेपाल के पोखरा में फेवाताल के पास अवैध निर्माण पर चला डोजर, बालेन्द्र शाह के निर्देश पर कार्रवाई

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के निर्देश पर पर्यटकीय शहर पोखरा में फेवाताल के आसपास बनाए गए अवैध टहरों (अस्थायी ढांचों) को पोखरा महानगरपालिका ने हटाना शुरू कर दिया है। पोखरा के मेयर धनराज आचार्य ने बताया कि बीती मध्यरात प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का फोन पर निर्देश मिलने पर महानगरपालिका ने शनिवार सुबह से डोजर चलाकर फेवाताल किनारे बने ढांचों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है।

महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापा के अनुसार, अब तक 32 टहरों को डोजर की मदद से गिराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई नेपाल पुलिस के सहयोग से की जा रही है। इससे पहले नवगठित संघीय सरकार ने फेवाताल क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को तीन महीने के भीतर हटाने का निर्णय लिया था। मंत्रिपरिषद की 100-सूत्रीय कार्ययोजना में भी इस मुद्दे को शामिल किया गया था। कार्रवाई के दौरान पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य के स्वामित्व वाले होटल वॉटरफ्रंट में भी डोजर चलाया गया। इस दौरान होटल का स्विमिंग पूल और गेट सहित कई संरचनाएं तोड़ी गईं। कास्की जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी हरि बहादुर बस्नेत के अनुसार, इस अभियान में जिला पुलिस, बैदाम पुलिस कार्यालय, महानगर प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के करीब 150 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस कार्रवाई पर कुछ स्थानीय निवासियों ने असंतोष भी व्यक्त किया है।

नेपाल के उद्योगपति शंकर अग्रवाल गिरफ्तार

काठमांडू। नेपाल के उद्योग समूह शंकर ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष शंकर लाल अग्रवाल को संपत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग) ने हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं अग्रवाल के दोनों बेटों साहिल अग्रवाल और सुलभा अग्रवाल के देश छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। संपत्ति शुद्धिकरण विभाग के तरफ से इमिग्रेशन विभाग को पत्र लिख कर दोनों के पासपोर्ट को निगरानी में रखने का निर्देश दिया गया है। बिचौलिया दीपक भट्ट के साथ मिलकर नीतिगत अनियमितताओं में संलिप्त होने के आरोपों के बीच विभाग ने जांच शुरू की, जिसके बाद शंकर अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया और साहिल तथा सुलभ अग्रवाल के पासपोर्ट को वाचलिस्ट के डाला गया है। व्यापारी दीपक भट्ट को दो दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। विभाग ने उन्हें शुक्रवार को कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की थी। बयान पूरा नहीं होने के कारण उन्हें ललितपुर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जिला ललितपुर के एसपी गौतम मिश्र ने बताया कि विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, 'विभाग ने हमें हिरासत में रखने के लिए भेजा है, लेकिन जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं है। विभाग ने शंकर ग्रुप से जुड़े बिचौलिया दीपक भट्ट को गुरुवार को ही गिरफ्तार किया था।

संक्षिप्त-समाचार

शातिर स्नैचर को पुलिस ने दबोचा

नई दिल्ली। पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने झपटमारी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाते हुए एक सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपित की गिरफ्तारी से पांच झपटमारी मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसके कब्जे से 40 हजार रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपित की पहचान बबलू (40) निवासी मदनगीर, दिल्ली के रूप में हुई है। वह लंबे समय से पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर और मयूर विहार इलाके में झपटमारी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पूर्वी जिला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती झपटमारी और चोरी की घटनाओं को देखते हुए स्पेशल स्टाफ को सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ का जिम्मा सौंपा गया था। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में गठित टीम ने स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय करते हुए संदिग्धों पर नजर रखी। दो अप्रैल को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास नोएडा लिंक रोड पर जाल बिछाकर आरोपित को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 40 हजार रुपये नकद बरामद हुए। मौके से एक बाइक जब्त की गई, जबकि उसकी निशानदेही पर एक अन्य बाइक भी बरामद कर ली गई। जांच में बरामद नकदी का संबंध मयूर विहार थाने में दर्ज एक मामले से पाया गया है। आरोपित से पूछताछ में पांडव नगर और मयूर विहार के कुल पांच झपटमारी मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, आरोपित पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उससे पूछताछ जारी है और अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।

रंगापाड़ा में हथियार के बल पर 22 लाख के आभूषण लूटे

शोणितपुर (असम)। शोणितपुर के रंगापाड़ा में बीती रात एक चौंकाने वाली घटना में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यवसायी से लगभग 22 लाख रुपये के सोने के आभूषण लूट लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नामनिगांव निवासी संतोष साह अपनी ज्वेलरी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने बंदूक दिखाकर उन्हें धमकाया, उनके साथ मारपीट की और आभूषण छीनकर फरार हो गए। यह घटना घर लौटने के दौरान रास्ते में हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश जारी है। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

पांच वर्षों में 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी भाजपा सरकार : पीयूष हजारिका

गुवाहाटी। असम में भाजपा की सरकार बनने पर अगले पांच वर्षों में दो लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। राज्य के मंत्री पीयूष हजारिका ने शनिवार को यह घोषणा की। प्रदेश भाजपा मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हजारिका ने कहा कि नौकरी के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी। मंत्री हजारिका ने उल्लेख किया कि सरकार ने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, हालांकि अब तक लगभग 1 लाख 65 हजार युवा-युवतियों को नौकरी प्रदान की जा चुकी है। कांग्रेस के समय नौकरी के क्षेत्र में जो व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) की नौकरियां क्षमता के बजाय धन और राजनीतिक प्रभाव पर निर्भर करती थीं। लेकिन अब वह परिस्थिति बदल गई है और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिली है। सरकार के पुनः शासन में आने पर 2 लाख नौकरियां प्रदान की जाएंगी, यह उन्होंने घोषणा की। यह बताते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकारी नौकरी के अलावा स्वरोजगार पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सके। 'मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम' योजना के तहत युवाओं को लगभग 2 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। आने वाले दिनों में 10 लाख बेरोजगारों को उद्यम शुरू करने के लिए लगभग 5 लाख रुपये की मदद देने का लक्ष्य रखा गया है। 'एडवांटेज असम' के माध्यम से 5.50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके माध्यम से टाटा के सेमिकंडक्टर परियोजना में 29 हजार दक्ष युवाओं को नौकरी मिलेगी। साथ ही उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले पांच वर्षों में 57 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त किताबें और 10 लाख विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान की गई हैं। छात्राओं के लिए 'निजुत मोइन' योजना के साथ ही अब 'निजुत बाबू' की भी व्यवस्था की गई है।

मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश 'गंजा' घायल, 75 से ज्यादा वारदातों में था शामिल

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिले के बदरपुर इलाके में शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और कुख्यात बदमाश मोहम्मद सलीम उर्फ 'गंजा' के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपित गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण-पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी के मुताबिक, मोहम्मद सलीम उर्फ 'गंजा' एक शातिर अपराधी है और उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी व सेंधमारी समेत 75 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 20 से ज्यादा मामलों में वांछित चल रहा था। आरोपित का नाम दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर सलीम पहलवान की हत्या में भी सामने आ चुका है। इसके अलावा वह गैंग के एक अन्य सदस्य की हत्या में भी शामिल रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित नासिर और दानिश पहलवान गिरोह का सक्रिय सदस्य है और लंबे समय से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस को आरोपित की बदरपुर क्षेत्र में मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद एसटीएफ टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपित को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। मौके से एक हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले 2024 बैच के आईएफएस अधिकारी

बिहार के हरित आवरण को 17% से आगे ले जाने का लक्ष्य

एजेंसी (हि.स.)
पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प सभागार' में आज वर्ष 2024 बैच के बिहार कैडर के भारतीय वन सेवा के 04 प्रशिक्षु अधिकारियों, हिमांशु द्विवेदी, प्रिंस कुमार सिंह, रविन्दर कुमार वर्मा एवं योगेश बोरकर ने मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि आप लोगों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए। आपलोग अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, उसके बाद आपलोगों की पोस्टिंग होगी। बिहार में हरित आवरण पहले मात्र 9 प्रतिशत था। राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से इसे बढ़ाकर 17 प्रतिशत तक पहुँचाया है। हरित आवरण को बढ़ाने में आप सभी अधिकारी सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से बिहार में वर्षापात कम हो रहा है इसलिये जल संचयन पर जोर देने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में ग्राउण्ड वाटर लेवल को संतुलित रखा जा सके।

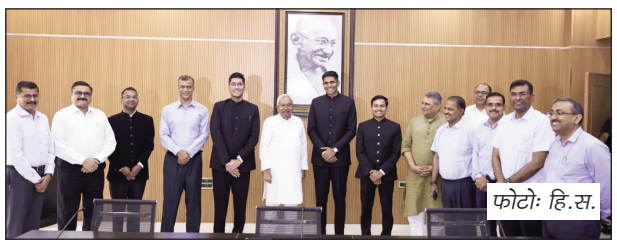
फोटोः हि.स.

शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने हेतु लोगों में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। आप सभी संवेदनशीलता, ईमानदारी, अनुशासन एवं पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हुये राज्य एवं देश की तरक्की में अपना योगदान दें। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने 4660 सहायक मतदान केंद्रों की दी मंजूरी

कोलकाता। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्य में 4,660 सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये केंद्र उन क्षेत्रों में बनाए जाएंगे जहां मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक है। इसके अलावा मतदाताओं की पहुंच आसान बनाने के लिए 321 मतदान केंद्रों के स्थान परिवर्तन को भी स्वीकृति दी गई है। इन नए प्रबंधों के बाद राज्य में कुल मतदान केंद्रों (सहायक केंद्रों सहित) की संख्या बढ़कर 85,379 हो गई है। चुनाव आयोग ने 28 मार्च के पत्र संख्या 3485-गृह (निर्वाचन) का हवाला देते हुए कहा है कि इन प्रस्तावों को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना में मतदान केंद्रों की पुस्तिका 2020 के पैरा 4.2.2 में दिए गए सभी दिशा-निदेर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इन बदलावों की लिखित सूचना दी जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदान केंद्र का स्थान बदला जाता है तो संबंधित क्षेत्र के सभी मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी देना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

मणिपुर में चार उग्रवादी गिरफ्तार राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजम

एजेंसी (हि.स.)
इंफाल

उग्रवादी गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए, मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने तेंगनौपाल जिले के मोरेह पुलिस स्टेशन के तहत यांगौबुंग गांव में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान घाटी-आधारित उग्रवादी समूह (वीबीआईजी) के चार कैडरों को गिरफ्तार किया है।

मणिपुर पुलिस द्वारा शनिवार को दी गयी आधिकारिक जानकारी के अनुसार चारों उग्रवादियों को बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। जिनकी पहचान केइशम सुमंता मैतेई (25, पीएलए से जुड़ा), अंगोम सोमरजीत सिंह उर्फ नोंगाबा (32, जो एनआरएफएम से जुड़ा), युमनाम नाओबा सिंह उर्फ शिनसांगम्बा (26, जो केसीपी/एमएफएल से जुड़ा) और खुंड्राकपम श्यामसन मैतेई उर्फ मंगनलेइबा (25, जो केसीपी /एमएफएल से जुड़ा) के रूप में की गयी है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई जिलों के सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और क्षेत्र पर नियंत्रण के अभ्यास तेज कर दिए हैं। इस बीच, अधिकारियों ने शुक्रवार को जरूरी सामानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की, जिसके तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-37 से कुल 276 वाहन गुजरे। सामानों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में काफिलों को सुरक्षा प्रदान की गई। बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के तहत, पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों में 117 नाके और चेकपॉइंट बनाए गए।

फोटोः हि.स.

होली पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला आरोपित गिरफ्तार, दो देशी कट्टे व कारतूस बरामद

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

होली के दिन फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने वाले आरोपित को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से दो देसी कट्टे और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपित घटना के बाद से फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान मुकुंदपुर निवासी शिवम उर्फ शिवा के रूप में हुई है। वह भलस्वा डेयरी थाने में दर्ज फायरिंग के एक मामले में वांछित था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आरोपित हाथ में दो कट्टे लेकर लोगों को धमकाता नजर आ रहा था। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, चार मार्च को होली के दिन मुकुंदपुर पार्ट-2 में आरोपित ने अरविंद कुमार पांडेय के साथ कहासुनी के बाद फायरिंग कर दी थी। आरोपित शराब के नशे में था और पहले गाली-गलौज करते हुए झगड़ा किया। इसके बाद वह दो देशी कट्टे लेकर लौटा और जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। हालांकि, पीड़ित बाल-बाल बच गया और घर के अंदर जाकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद आरोपित ने इलाके में हंगामा किया और खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। मामले में भलस्वा डेयरी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

फोटोः हि.स.

पुलिस उपायुक्त के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपित की पहचान कर उसकी तलाश शुरू की। लगातार निगरानी के बाद तीन अप्रैल को क्राइम ब्रांच यूईआर-2 के पास छापेमारी कर आरोपित को दबोच लिया।

रोष

ओडिशा की रेल संपदा पर छिड़ा सियासी घमासान

पालासा-इच्छापुरम खंड को साउथ कोस्ट रेलवे में शामिल करने का पुरजोर विरोध

एजेंसी (हि.स.)
भुवनेश्वर

ओडिशा में विभिन्न राजनीतिक दलों ने रेलवे बोर्ड के उस निर्णय का कड़ा विरोध किया है, जिसमें पालासा-इच्छापुरम रेल खंड को ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकार क्षेत्र से हटाकर प्रस्तावित साउथ कोस्ट रेलवे जोन में शामिल करने की बात कही गई है। दलों ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

यह रेल खंड वर्तमान में ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत आता है, लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार इसे साउथ कोस्ट रेलवे के विशाखापट्टनम मंडल में शामिल करने का प्रस्ताव है। बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा कोयला, खनिज और औद्योगिक उत्पादन के माध्यम से भारतीय रेलवे के माल राजस्व में बड़ा योगदान देता है, ऐसे में इस तरह के बदलाव से राज्य को वित्तीय और प्रशासनिक नुकसान हो सकता है। पात्रा ने चेतावनी दी कि अधिक राजस्व वाले रेल खंडों को ईस्ट कोस्ट रेलवे से हटाने से रेलवे योजना और प्राथमिकताओं में ओडिशा की भूमिका कमजोर हो सकती है, साथ ही प्रशासनिक दक्षता पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि राज्य से जुड़े किसी भी फैसले से पहले जनप्रतिनिधियों और हितधारकों से परामर्श किया जाए। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे राज्य के साथ 'सौतेला व्यवहार' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद ओडिशा को बुनियादी ढांचे के विकास में नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि उसकी महत्वपूर्ण संपत्तियों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन के अधिकार क्षेत्र की समीक्षा की गई है और संशोधित योजना के तहत पालासा-इच्छापुरम खंड को विशाखापट्टनम मंडल में शामिल किया जाएगा। इस फैसले को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर भी चिंता सामने आई है। ब्रह्मपुर के सांसद प्रदीप कुमार पाणिग्रही ने इस रेल खंड को दक्षिण ओडिशा की 'आर्थिक धुरी' बताते हुए कहा कि इसके स्थानांतरण से लॉजिस्टिक्स और राजस्व प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

फोटोः हि.स.

ईरान ने इजराइल पर किया हवाई हमला, तीन शहरों में नुकसान

इजराइल के शहरों में मची अफरा-तफरी: बिजली गुल और इमारतें जमींदोज

एजेंसी (हि.स.)
तेल अवीव/ तेहरान

ईरान 28 फरवरी से अमेरिका-इजराइल के साथ छिड़े युद्ध में बहुत कुछ खोने के बावजूद दुश्मन को नाकों चने चबवा रहा है। राजधानी तेहरान के पश्चिम में स्थित करज में गुरुवार को महत्वपूर्ण पुल पर किए गए हमले के बाद ईरान आक्रामक हो गया है। उसने आज तड़के इजराइल के तीन शहरों पर हवाई हमला किया है। इसके अलावा अमेरिका का एक और विमान मार गिराने का दावा किया है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने रामत गान में बमबारी की है। इस बमबारी में एक इमारत ढह गई है। इसके अलावा रोश हा'यिन में किए गए हमले में बिजली गुल हो गई। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने इसकी

फोटोः हि.स.

पुष्टि की है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस का कहना है कि ईरान ने बीरशेबा के दक्षिण में स्थित नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसके अलावा बेनी ब्राक में हुए हमले में एक व्यक्ति को हल्की चोट आई आई है। उसे इलाज के लिए मयानेई हयेशुआ मेडिकल सेंटर ले जाया गया। अल जजीरा चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, करज में गुरुवार को महत्वपूर्ण पुल पर किए गए हमले के बाद ईरान ने शुक्रवार को एक अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराया। तेहरान ने आज सुबह दावा किया कि उसकी सेना ने अमेरिका के दूसरे विमान (ए-10) को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मार गिराया। इस बीच अमेरिका के ईरान में प्रमुख पुल को नष्ट करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब नागरिक सुविधाओं और बिजली संयंत्रों पर हमले झेलने के लिए तेहरान तैयार रहे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ट्रंप की धमकी को 'बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध' करने के इरादे की स्वीकारोक्ति बताया है। कुवैत ने कहा है कि ईरान ने एक जल विलवणीकरण संयंत्र और एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है।

तेहरान ने विलवणीकरण संयंत्र को

ईरान ने एक और अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया

तेहरान/वाशिंगटन। ईरान 28 फरवरी से अमेरिका-इजराइल के साथ छिड़े युद्ध में बहुत कुछ खोने के बावजूद दुश्मन को नाकों चने चबवा रहा है। राजधानी तेहरान के पश्चिम में स्थित करज में गुरुवार को महत्वपूर्ण पुल पर किए गए हमले के बाद ईरान ने शुक्रवार को एक अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराया। तेहरान ने आज सुबह दावा किया कि उसकी सेना ने अमेरिका का एक और विमान गिरा दिया है। अल जजीरा चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के दूसरे विमान (ए-10) को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मार गिराया। इस बीच अमेरिका के ईरान में प्रमुख पुल को नष्ट करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब नागरिक सुविधाओं और बिजली संयंत्रों पर हमले झेलने के लिए तेहरान तैयार रहे।ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ट्रंप की धमकी को 'बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध' करने के इरादे की स्वीकारोक्ति बताया है। कुवैत ने कहा है कि ईरान ने एक जल विलवणीकरण संयंत्र और एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। तेहरान ने विलवणीकरण संयंत्र को इजराइल पर भी मिसाइलें दागी हैं। 28 फरवरी से अब तक, पूरे ईरान में अमेरिकी-इजराइली हमलों में कम से कम 2,076 लोग मारे गए हैं और 26,500 घायल हुए हैं।

काठमांडू में पुलिस का रातभर चला सर्च ऑपरेशन, 195 लोग गिरफ्तार

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुलिस ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाकर बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। गुंडागर्दी, ठगी और बिचौलियागिरी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। काठमांडू के एसएसपी रमेश थापा के अनुसार, शहर के विभिन्न स्थानों से कुल 195 लोगों को पकड़ा गया। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठमेल और बुढानीलकण्ठ समेत विभिन्न क्षेत्रों से इन लोगों को हिरासत में लिया गया।

एसएसपी थापा ने बताया, 'ठमेल और विमानस्थल जैसे इलाकों में यात्रियों को खींचतान करने वाले, पहले से गुंडागर्दी में शामिल और बिचौलिया गतिविधियों में लगे 195 लोगों को नियंत्रण में लिया गया है।' पुलिस के अनुसार, इन सभी के खिलाफ आगे की जांच जारी है। वहीं, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें यात्रियों को जबरन खींचने (कस्टमर पकड़ने) के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में टैक्सी चालक और होटल प्रतिनिधि शामिल हैं।

मकवानपुर में ट्रक पलटने से त्रिभुवन राजपथ अवरुद्ध

काठमांडू। नेपाल में मकवानपुर के थाहा नगरपालिका-12 टिस्टुड स्थित त्रिभुवन राजपथ पर बीती रात लगभग डेढ़ बजे ट्रक (बा.प्र.03-001 ख 1750) पलटने से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। यह ट्रक काठमांडू से हेटौंडा की ओर जा रहा था। जिला पुलिस कार्यालय मकवानपुर के अनुसार, ट्रक आगे दाहिने हिस्से का पट्टा (मैकेनिकल हिस्सा) टूटने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया।इस दुर्घटना में ट्रक चालक धादिंग के बेनिघाट मौवाखोला निवासी लगभग 27 वर्षीय ध्रुब घले घायल हो गए।। ट्रक से कूदने के दौरान उनके दाहिने पैर के तलवे में चोट लगी है। उन्हें इलाज के लिए पालुङ अस्पताल भेजा गया है। मकवानपुर पुलिस के प्रवक्ता डीएसपी पुष्कर बोगटी ने जानकारी दी कि सड़क खोलने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के अभी भी घटनास्थल पर ही होने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित है। सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है।

पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कटौती नया भाव 378 रुपये प्रति लीटर

एजेंसी (हि.स.)
इस्लामाबाद

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में शरीफ ने कहा कि पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। यह एक महीने तक लागू रहेगी। यह कटौती पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये प्रति लीटर की कमी के बाद की गई है।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में सरकार ने राष्ट्रीय संसाधनों से 129 अरब रुपये की सब्सिडी दी है। इन उपायों का उद्देश्य ईंधन की बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ जनता पर पड़ने से रोकना है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्षित सब्सिडी की भी घोषणा की है। मोटरसाइकिल चालकों को 100 रुपये प्रति लीटर की

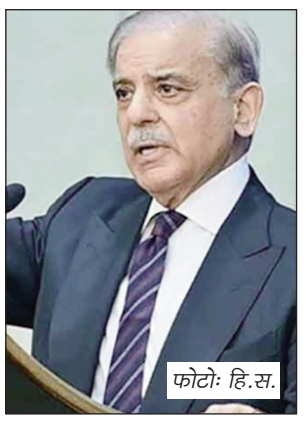
फोटोः हि.स.

सब्सिडी दी जाएगी।

परिवहन क्षेत्र को भी राहत उपायों में शामिल किया गया है। बढ़ते परिचालन खर्चों की भरपाई के लिए मालवाहक और कमर्शियल वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन बसों को हर महीने 100,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, ताकि यात्रियों के लिए किराया स्थिर रखा जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि इकोनॉमी-क्लास ट्रेन यात्रा का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा।

नेपाल के पोखरा में फेवाताल के पास अवैध निर्माण पर चला डोजर, बालेन्द्र शाह के निर्देश पर कार्रवाई

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के निर्देश पर पर्यटकीय शहर पोखरा में फेवाताल के आसपास बनाए गए अवैध टहरों (अस्थायी ढांचों) को पोखरा महानगरपालिका ने हटाना शुरू कर दिया है। पोखरा के मेयर धनराज आचार्य ने बताया कि बीती मध्यरात प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का फोन पर निर्देश मिलने पर महानगरपालिका ने शनिवार सुबह से डोजर चलाकर फेवाताल किनारे बने ढांचों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है।

महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापा के अनुसार, अब तक 32 टहरों को डोजर की मदद से गिराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई नेपाल पुलिस के सहयोग से की जा रही है। इससे पहले नवगठित संघीय सरकार ने फेवाताल क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को तीन महीने के भीतर हटाने का निर्णय लिया था। मंत्रिपरिषद की 100-सूत्रीय कार्ययोजना में भी इस मुद्दे को शामिल किया गया था। कार्रवाई के दौरान पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य के स्वामित्व वाले होटल वॉटरफ्रंट में भी डोजर चलाया गया। इस दौरान होटल का स्विमिंग पूल और गेट सहित कई संरचनाएं तोड़ी गईं। कास्की जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी हरि बहादुर बस्नेत के अनुसार, इस अभियान में जिला पुलिस, बैदाम पुलिस कार्यालय, महानगर प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के करीब 150 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस कार्रवाई पर कुछ स्थानीय निवासियों ने असंतोष भी व्यक्त किया है।

नेपाल के उद्योगपति शंकर अग्रवाल गिरफ्तार

काठमांडू। नेपाल के उद्योग समूह शंकर ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष शंकर लाल अग्रवाल को संपत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग) ने हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं अग्रवाल के दोनों बेटों साहिल अग्रवाल और सुलभा अग्रवाल के देश छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। संपत्ति शुद्धिकरण विभाग के तरफ से इमिग्रेशन विभाग को पत्र लिख कर दोनों के पासपोर्ट को निगरानी में रखने का निर्देश दिया गया है। बिचौलिया दीपक भट्ट के साथ मिलकर नीतिगत अनियमितताओं में संलिप्त होने के आरोपों के बीच विभाग ने जांच शुरू की, जिसके बाद शंकर अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया और साहिल तथा सुलभ अग्रवाल के पासपोर्ट को वाचलिस्ट के डाला गया है। व्यापारी दीपक भट्ट को दो दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। विभाग ने उन्हें शुक्रवार को कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की थी। बयान पूरा नहीं होने के कारण उन्हें ललितपुर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जिला ललितपुर के एसपी गौतम मिश्र ने बताया कि विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, 'विभाग ने हमें हिरासत में रखने के लिए भेजा है, लेकिन जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं है। विभाग ने शंकर ग्रुप से जुड़े बिचौलिया दीपक भट्ट को गुरुवार को ही गिरफ्तार किया था।

संक्षिप्त-समाचार

शातिर स्नैचर को पुलिस ने दबोचा

नई दिल्ली। पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने झपटमारी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाते हुए एक सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपित की गिरफ्तारी से पांच झपटमारी मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसके कब्जे से 40 हजार रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपित की पहचान बबलू (40) निवासी मदनगीर, दिल्ली के रूप में हुई है। वह लंबे समय से पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर और मयूर विहार इलाके में झपटमारी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पूर्वी जिला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती झपटमारी और चोरी की घटनाओं को देखते हुए स्पेशल स्टाफ को सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ का जिम्मा सौंपा गया था। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में गठित टीम ने स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय करते हुए संदिग्धों पर नजर रखी। दो अप्रैल को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास नोएडा लिंक रोड पर जाल बिछाकर आरोपित को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 40 हजार रुपये नकद बरामद हुए। मौके से एक बाइक जब्त की गई, जबकि उसकी निशानदेही पर एक अन्य बाइक भी बरामद कर ली गई। जांच में बरामद नकदी का संबंध मयूर विहार थाने में दर्ज एक मामले से पाया गया है। आरोपित से पूछताछ में पांडव नगर और मयूर विहार के कुल पांच झपटमारी मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, आरोपित पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उससे पूछताछ जारी है और अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।

रंगापाड़ा में हथियार के बल पर 22 लाख के आभूषण लूटे

शोणितपुर (असम)। शोणितपुर के रंगापाड़ा में बीती रात एक चौंकाने वाली घटना में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यवसायी से लगभग 22 लाख रुपये के सोने के आभूषण लूट लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नामनिगांव निवासी संतोष साह अपनी ज्वेलरी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने बंदूक दिखाकर उन्हें धमकाया, उनके साथ मारपीट की और आभूषण छीनकर फरार हो गए। यह घटना घर लौटने के दौरान रास्ते में हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश जारी है। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

पांच वर्षों में 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी भाजपा सरकार : पीयूष हजारिका

गुवाहाटी। असम में भाजपा की सरकार बनने पर अगले पांच वर्षों में दो लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। राज्य के मंत्री पीयूष हजारिका ने शनिवार को यह घोषणा की। प्रदेश भाजपा मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हजारिका ने कहा कि नौकरी के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी। मंत्री हजारिका ने उल्लेख किया कि सरकार ने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, हालांकि अब तक लगभग 1 लाख 65 हजार युवा-युवतियों को नौकरी प्रदान की जा चुकी है। कांग्रेस के समय नौकरी के क्षेत्र में जो व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) की नौकरियां क्षमता के बजाय धन और राजनीतिक प्रभाव पर निर्भर करती थीं। लेकिन अब वह परिस्थिति बदल गई है और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिली है। सरकार के पुनः शासन में आने पर 2 लाख नौकरियां प्रदान की जाएंगी, यह उन्होंने घोषणा की। यह बताते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकारी नौकरी के अलावा स्वरोजगार पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सके। 'मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम' योजना के तहत युवाओं को लगभग 2 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। आने वाले दिनों में 10 लाख बेरोजगारों को उद्यम शुरू करने के लिए लगभग 5 लाख रुपये की मदद देने का लक्ष्य रखा गया है। 'एडवांटेज असम' के माध्यम से 5.50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके माध्यम से टाटा के सेमिकंडक्टर परियोजना में 29 हजार दक्ष युवाओं को नौकरी मिलेगी। साथ ही उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले पांच वर्षों में 57 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त किताबें और 10 लाख विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान की गई हैं। छात्राओं के लिए 'निजुत मोइन' योजना के साथ ही अब 'निजुत बाबू' की भी व्यवस्था की गई है।

मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश 'गंजा' घायल, 75 से ज्यादा वारदातों में था शामिल

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिले के बदरपुर इलाके में शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और कुख्यात बदमाश मोहम्मद सलीम उर्फ 'गंजा' के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपित गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण-पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी के मुताबिक, मोहम्मद सलीम उर्फ 'गंजा' एक शातिर अपराधी है और उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी व सेंधमारी समेत 75 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 20 से ज्यादा मामलों में वांछित चल रहा था। आरोपित का नाम दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर सलीम पहलवान की हत्या में भी सामने आ चुका है। इसके अलावा वह गैंग के एक अन्य सदस्य की हत्या में भी शामिल रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित नासिर और दानिश पहलवान गिरोह का सक्रिय सदस्य है और लंबे समय से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस को आरोपित की बदरपुर क्षेत्र में मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद एसटीएफ टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपित को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। मौके से एक हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले 2024 बैच के आईएफएस अधिकारी

बिहार के हरित आवरण को 17% से आगे ले जाने का लक्ष्य

एजेंसी (हि.स.)
पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प सभागार' में आज वर्ष 2024 बैच के बिहार कैडर के भारतीय वन सेवा के 04 प्रशिक्षु अधिकारियों, हिमांशु द्विवेदी, प्रिंस कुमार सिंह, रविन्दर कुमार वर्मा एवं योगेश बोरकर ने मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि आप लोगों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए। आपलोग अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, उसके बाद आपलोगों की पोस्टिंग होगी। बिहार में हरित आवरण पहले मात्र 9 प्रतिशत था। राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से इसे बढ़ाकर 17

फोटोः हि.स.

प्रतिशत तक पहुँचाया है। हरित आवरण को बढ़ाने में आप सभी अधिकारी सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से बिहार में वर्षापात कम हो रहा है इसलिये जल संचयन पर जोर देने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में ग्राउण्ड वाटर लेवल को संतुलित रखा जा सके।

शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने हेतु लोगों में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। आप सभी संवेदनशीलता, ईमानदारी, अनुशासन एवं पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हुये राज्य एवं देश की तरक्की में अपना योगदान दें। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने 4660 सहायक मतदान केंद्रों की दी मंजूरी

कोलकाता। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्य में 4,660 सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये केंद्र उन क्षेत्रों में बनाए जाएंगे जहां मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक है। इसके अलावा मतदाताओं की पहुंच आसान बनाने के लिए 321 मतदान केंद्रों के स्थान परिवर्तन को भी स्वीकृति दी गई है। इन नए प्रबंधों के बाद राज्य में कुल मतदान केंद्रों (सहायक केंद्रों सहित) की संख्या बढ़कर 85,379 हो गई है। चुनाव आयोग ने 28 मार्च के पत्र संख्या 3485-गृह (निर्वाचन) का हवाला देते हुए कहा है कि इन प्रस्तावों को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना में मतदान केंद्रों की पुस्तिका 2020 के पैरा 4.2.2 में दिए गए सभी दिशा-निदेर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इन बदलावों की लिखित सूचना दी जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदान केंद्र का स्थान बदला जाता है तो संबंधित क्षेत्र के सभी मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी देना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

मणिपुर में चार उग्रवादी गिरफ्तार राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजम

एजेंसी (हि.स.)
इंफाल

उग्रवादी गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए, मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने तेंगनौपाल जिले के मोरेह पुलिस स्टेशन के तहत यांगौबुंग गांव में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान घाटी-आधारित उग्रवादी समूह (वीबीआईजी) के चार कैडरों को गिरफ्तार किया है।

मणिपुर पुलिस द्वारा शनिवार को दी गयी आधिकारिक जानकारी के अनुसार चारों उग्रवादियों को बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। जिनकी पहचान केइशम सुमंता मैतेई (25, पीएलए से जुड़ा), अंगोम सोमरजीत सिंह उर्फ नोंगाबा (32, जो एनआरएफएम से जुड़ा), युमनाम नाओबा सिंह उर्फ शिनसांगम्बा (26, जो केसीपी/एमएफएल से जुड़ा) और खुंड्राकपम श्यामसन मैतेई उर्फ मंगनलेइबा (25, जो केसीपी /एमएफएल से जुड़ा) के रूप में की

फोटोः हि.स.

गयी है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई जिलों के सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और क्षेत्र पर नियंत्रण के अभ्यास तेज कर दिए हैं। इस बीच, अधिकारियों ने शुक्रवार को जरूरी सामानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की, जिसके तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-37 से कुल 276 वाहन गुजरे। सामानों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में काफिलों को सुरक्षा प्रदान की गई। बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के तहत, पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों में 117 नाके और चेकपॉइंट बनाए गए।

होली पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला आरोपित गिरफ्तार, दो देशी कट्टे व कारतूस बरामद

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

होली के दिन फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने वाले आरोपित को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से दो देसी कट्टे और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपित घटना के बाद से फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान मुकुंदपुर निवासी शिवम उर्फ शिवा के रूप में हुई है। वह भलस्वा डेयरी थाने में दर्ज फायरिंग के एक मामले में वांछित था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आरोपित हाथ में दो कट्टे लेकर लोगों को धमकाता नजर आ रहा था। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, चार मार्च को होली के दिन मुकुंदपुर पार्ट-2 में आरोपित ने अरविंद कुमार पांडेय के साथ कहासुनी के बाद फायरिंग कर दी थी। आरोपित शराब के नशे में था और पहले गाली-गलौज करते हुए झगड़ा किया। इसके बाद वह

फोटोः हि.स.

दो देशी कट्टे लेकर लौटा और जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। हालांकि, पीड़ित बाल-बाल बच गया और घर के अंदर जाकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद आरोपित ने इलाके में हंगामा किया और खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। मामले में भलस्वा डेयरी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

पुलिस उपायुक्त के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपित की पहचान कर उसकी तलाश शुरू की। लगातार निगरानी के बाद तीन अप्रैल को क्राइम ब्रांच यूईआर-2 के पास छापेमारी कर आरोपित को दबोच लिया।

रोष

ओडिशा की रेल संपदा पर छिड़ा सियासी घमासान

पालासा-इच्छापुरम खंड को साउथ कोस्ट रेलवे में शामिल करने का पुरजोर विरोध

एजेंसी (हि.स.)
भुवनेश्वर

ओडिशा में विभिन्न राजनीतिक दलों ने रेलवे बोर्ड के उस निर्णय का कड़ा विरोध किया है, जिसमें पालासा-इच्छापुरम रेल खंड को ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकार क्षेत्र से हटाकर प्रस्तावित साउथ कोस्ट रेलवे जोन में शामिल करने की बात कही गई है। दलों ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

यह रेल खंड वर्तमान में ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत आता है, लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार इसे साउथ कोस्ट रेलवे के विशाखापट्टनम मंडल में शामिल करने का प्रस्ताव है। बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए

फोटोः हि.स.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा कोयला, खनिज और औद्योगिक उत्पादन के माध्यम से भारतीय रेलवे के माल राजस्व में बड़ा योगदान देता है, ऐसे में इस तरह के बदलाव से राज्य को वित्तीय और प्रशासनिक नुकसान हो सकता है। पात्रा ने चेतावनी दी कि अधिक राजस्व वाले रेल खंडों को ईस्ट कोस्ट रेलवे से हटाने से रेलवे योजना और प्राथमिकताओं में ओडिशा की भूमिका कमजोर हो सकती है, साथ ही प्रशासनिक दक्षता पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि राज्य से जुड़े किसी भी फैसले से पहले जनप्रतिनिधियों और हितधारकों से परामर्श किया जाए। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे राज्य के साथ 'सौतेला व्यवहार' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद ओडिशा को बुनियादी ढांचे के विकास में नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि उसकी महत्वपूर्ण संपत्तियों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन के अधिकार क्षेत्र की समीक्षा की गई है और संशोधित योजना के तहत पालासा-इच्छापुरम खंड को विशाखापट्टनम मंडल में शामिल किया जाएगा। इस फैसले को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर भी चिंता सामने आई है। ब्रह्मपुर के सांसद प्रदीप कुमार पाणिग्रही ने इस रेल खंड को दक्षिण ओडिशा की 'आर्थिक धुरी' बताते हुए कहा कि इसके स्थानांतरण से लॉजिस्टिक्स और राजस्व प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी अनाज मंडियों का किया दौरा

गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी अनाज मंडियों का दौरा कर रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। मंत्री ने मंडियों में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, फसल सत्यापन प्रक्रिया, बिजली, पानी, साफ-सफाई और बायोमैट्रिक प्रणाली सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। जिले की पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी मंडियों में खाद्यान की खरीद का कार्य राज्य खरीद एजेंसी हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देश हैं कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से सभी मंडियों में खरीद कार्य को सुचारू और निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने निर्देश दिए कि जिला की तीनो मंडियों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और फसल आते ही उठान कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही, उन्होंने किसानों को फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि रबी खरीद सीजन 2026 के दौरान किसानों को सुविधा प्रदान करने, समय की बचत करने तथा खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। उन्होने बताया कि किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर-ट्रॉली के अतिरिक्त अन्य पारंपरिक साधनों जैसे बैलगाड़ी आदि के माध्यम से भी मंडी में ला सकते हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन में तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में किसान अथवा उसके नामित व्यक्तियों का सत्यापन ओटीपी माध्यम से किया जाएगा। पूरी खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री अजय मितल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक श्री राकेश पोरिया, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्री जतिन मितल, चैयरमेन मार्किट कमेटी पंचकूला श्री सुरेद्रं शर्मा, चैयरमेन मार्किट कमेटी बरवाला श्री देशराज पोसवाल, चैयरमेन मार्किट कमेटी रायपुररानी श्री पंचराम सैनी, पंचकूला मार्केट कमेटी सचिव श्री बलदीप सिंह, सचिव मार्किट कमेटी बरवाला श्री सुरेंद्र सिंह, कृषि विभाग के एसडीओ श्री जितेंद्र कुमार सहित हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

विधायक कुलवंत सिंह ने मोहाली से 18वीं बस को हरी झंडी देकर किया रवाना

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

विधायक कुलवंत सिंह ने आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र मोहाली से 18वीं बस को हरी झंडी दिखाई। ब्लॉक अध्यक्ष कुलवंत कौर कोमल के नेतृत्व में इस बस को हरी झंडी दिखाते हुए विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा राज्य के लोगों से किए गए सभी वादे और गारंटी पूरी कर दी गई हैं और इससे भी आगे बढ़कर, लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का स्थायी रूप से समाधान किया जा रहा है, जबकि पंजाब में विकास की गति और तेज हो गई है।

इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत पूरे पंजाब से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन श्री दरबार साहिब, दुर्गियाना मंदिर, राम तीर्थ वाल्मीकि मंदिर, जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर जा रहे हैं और जैसे ही दूसरे लोगों को इस तीर्थ यात्रा के बारे में पता चलता है, वे तुरंत बूथ इंचार्जों को पूरे जोश के साथ तीर्थ यात्रा को लेकर रजिस्टर कर रहे हैं और सरकार ने श्रद्धालुओं के आने-जाने और ठहरने का पूरा इंतजाम किया है। किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। मेडिकल एक्सपर्ट और गाइड भी हर समय श्रद्धालुओं के साथ मौजूद रहते हैं, जबकि विरोधी पार्टी के नेता तीर्थ यात्रा के दौरान हुल्लड़बाजी की बे-बुनियाद व झूठी बात बात कर रहे है,, क्योंकि अब विरोधियों के पास झूठ के अलावा कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि जब श्रद्धालु पवित्र श्री दरबार साहिब, दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि मंदिर राम तीर्थ जाते हैं, तो सबका सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। इस मौके पर हुलरास सिंह के अलावा सुरिंदर सिंह रोड़ा सुहाना, नंबरदार हरसंगत सिंह सुहाना, जगदीश सिंह सुहाना जगतार सिंह, जसविंदर सिंह पिंका, सुखदेव सिंह सुहाना, मनोहर सिंह सुहाना, रणधीर सिंह सुहाना, सतनाम सिंह सुहाना, मान सिंह, अमर सिंह, मनोहर लाल, हरि किशोर, सुखदेव सिंह, परमिंदर सिंह, निर्मल सिंह, कुलवंत सिंह भी मौजूद थे।

मानवाधिकार लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यू.टी.) मानवाधिकार आयोग द्वारा 04 अप्रैल 2026 को म्यूनिसिपल भवन, सेक्टर 35, चंडीगढ़ में मानवाधिकार लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में गणमान्य व्यक्तियों, न्यायपालिका के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकताओं तथा पंजाब और चंडीगढ़ के विभिन्न जिलों से कोर ग्रुप सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में माननीय श्री न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथियों में माननीय सुश्री राज लाली गिल, अध्यक्षा, पंजाब राज्य महिला आयोग; माननीय गुरजीत कौर रूचि बावा, उपाध्यक्ष, पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग; श्री गौरव यादव, आईपीएस, डीजीपी पंजाब; तथा डॉ. सागर प्रीत हुड्डा, आईपीएस, डीजीपी चंडीगढ़ शामिल रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत कोर ग्रुप सदस्यों के पंजीकरण से हुई, जिसके बाद उद्घाटन सत्र राष्ट्रीय गान और दीप प्रज्वलन समारोह से आरंभ हुआ, जिसके पश्चात भांगड़ा प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों द्वारा सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस कॉन्क्लेव की मुख्य विशेषता कोर ग्रुप सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और उनका औपचारिक शामिल किया जाना रहा। ये सदस्य आयोग के जमीनी स्तर पर कार्यों की रीढ़ हैं। ये सदस्य विभिन्न जिलों और चंडीगढ़ से संबंधित हैं और आयोग के विस्तारित हाथ के रूप में कार्य करते हैं, जो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की पहचान करने, जागरूकता फैलाने और जनता तथा आयोग के बीच संवाद स्थापित करने में सहायता करते हैं।

नगर निगम सफाई, बेहतर नागरिक अवसंरचना और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

सफाई, बेहतर नागरिक अवसंरचना और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, आयुक्त श्री विनय कुमार के नेतृत्व में पंचकूला नगर निगम ने 7 अप्रैल से 16 अप्रैल 2026 तक विभिन्न वार्डों और सेक्टरों में प्रातः कालीन निरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। इस कार्यक्रम के अनुसार, आयुक्त श्री विनय कुमार सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। श्री विनय कुमार 7 अप्रैल झवार्ड नंबर 12, सेक्टर 2; 8 अप्रैल झ वार्ड नंबर 11, सेक्टर 4; 9 अप्रैल झ वार्ड नंबर 11, सेक्टर 11; 10 अप्रैल झ वार्ड नंबर 14 और 15, सेक्टर 20; 13 अप्रैल झ वार्ड नंबर 13, सेक्टर 21; 15 अप्रैल झ वार्ड नंबर 17, सेक्टर 25; और 16 अप्रैल झ वार्ड नंबर 18, सेक्टर 26 का निरीक्षण करेंगे। सभी निरीक्षण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे। इन निरीक्षणों के दौरान प्रमुख नागरिक मापदंडों की गहन समीक्षा की जाएगी, जिसमें घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना, स्वच्छता के मानक, चल रहे विकास कार्यों की स्थिति, अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे और निरीक्षण के दौरान निवासियों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे शामिल हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड और अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित स्थलों पर उपस्थित रहें। यह औचक निरीक्षण इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि पिछले निरीक्षणों में सुझाए गए सुधार लगातार बनाए रखें जाएँ और फील्ड टीमें स्वच्छता व सेवा मानकों का निरंतर पालन करें। उन्होंने कहा की नगर निगम, पंचकूला के सभी निवासियों से अपील करता है कि वे इन प्रयासों में सक्रिय सहयोग करें। नागरिकों को कचरे के उचित निपटान की आदत अपनाने, इधर-उधर कूड़ा न फैलाने, अतिक्रमण से बचने तथा अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, हरित और सुव्यवस्थित पंचकूला का लक्ष्य सामूहिक जिम्मेदारी और जनभागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर निगम इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा और सभी संबंधित पक्षों से निरंतर सहयोग की अपेक्षा करता है।

संक्षिप्त-समाचार

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रोहित कपूर द्वारा जिला न्यायालय चंडीगढ़ का वार्षिक निरीक्षण, वृक्षारोपण, पार्किंग स्थल का दौरा और बार सदस्यों के साथ संवाद।

हिंदू पर्व महासभा ने प्रशासन से भिखारियों पर लगाम लगाने की मांग की

चंडीगढ़। श्री बीपी अरोड़ा अध्यक्ष एवं श्री कमलेश चंद्र सूरी महासचिव ने बताया कि आजकल ज्यादातर चंडीगढ़ में मंदिरों के आगे मांगने वाले /भिखारी खड़े रहते हैं जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं, लड़कियां व बच्चे शामिल है और उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अक्सर वह आपस में लड़ते व चिल्लाते पाए जाते हैं। उनसे भक्तों एवं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में अंदर जाने हेतु एवं पार्किंग के लिए काफी मुश्किले आती है। सामान्यतय वह आने वाले श्रद्धालुओं के पीछे भागते हैं और मांगते हुए उनके सामान छीनने/ झपटने का प्रयास करते हैं। इनकी बढ़ती संख्या देखकर मंदिर सभाओं को यह डर भी रहता है कि कहीं कोई उनके मंदिरों की रेकी तो नहीं कर रहा। इसके अतिरिक्त भविष्य में मंदिरों में चोरी का भी डर लगा रहता है। श्री अरोड़ा जी एवं श्री सूरी जी ने कहा कि मांगने वालों भिखारियों को हटाने हेतु चंडीगढ़ पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए ताकि भविष्य में मंदिरों में कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा हेतु मंदिरों के आगे अधिक से अधिक पुलिस गश्त बढ़ाने का आश्वासन मांगा और तुरंत आवश्यक, सख्त एवं उचित कदम उठाने को कहा।

नवजात तंत्रिका संबंधी विकार पर एकल-विषय कार्यशाला

चंडीगढ़। नवजात तंत्रिका संबंधी विकार पर एकल-विषयक कार्यशाला का शुभारंभ पीजीआईएमईआर के एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर के ऑडिटोरियम में हुआ। पीजीआईएमईआर के माननीय निदेशक प्रो. विवेक लाल ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। पीजीआईएमईआर के पूर्व बाल चिकित्सा एवं नवजात विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. ओ. एन. भाकू ने भी उद्घाटन सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रो. विवेक लाल – जो स्वयं एक प्रतिष्ठित वयस्क तंत्रिका रोग विशेषज्ञ हैं – ने इस चुनौतीपूर्ण विषय पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए नवजात इकाई की सराहना की। उन्होंने अपने प्रशिक्षण काल की कई रोचक घटनाएँ साझा करते हुए यह बताया कि ठोस नैदानिक ज्ञान को आधुनिक जाँच विधियों के साथ संयोजित करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रो. सौरभ दत्ता ने नवजात मेनिन्जाइटिस के निदान व उपचार में होने वाली त्रुटियों और जटिलताओं पर अपने विचार रखे। इस व्यावहारिक सत्रों में बढ़ तीन वास्तविक केस परिदृश्यों पर समूह-चर्चाएँ हुईं, जिनमें विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क समस्याओं वाले नवजात शिशुओं के मामले शामिल थे। प्रतिभागियों को विशेषज्ञों से एक-एक कर बातचीत करने का अवसर मिला। इन केस परिदृश्यों में आवश्यकतानुसार नैदानिक विवरण, प्रयोगशाला रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड तथा एमआरआई चित्र भी सम्मिलित थे।

बैंक ऑफ इंडिया ने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकूला में नई शाखा खोलकर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया

पंचकूला। उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बैंक ऑफ इंडिया ने आज मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकूला, हरियाणा में एक नई शाखा का उद्घाटन किया। यह विस्तार पूरे क्षेत्र में ग्राहकों को सुलभता प्रदान करने और गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रति बैंक ऑफ इंडिया की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा एक प्रमुख विकास क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहां तीव्र शहरीकरण और आर्थिक विकास हो रहा है। इस क्षमता को पहचानते हुए, बैंक ऑफ इंडिया राज्य भर में नई शाखाएं खोलकर सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन और क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति में योगदान मिल रहा है। उद्घाटन समारोह में माननीय महाप्रबंधक - श्री अनिल कुमार वर्मा (एफजीएमओ चंडीगढ़) उपस्थित थे। इस अवसर पर आंचलिक प्रबंधक चंडीगढ़ अंचल श्री राजेश रंजन, डीजीएम ऑडिट श्री मोती लाल और उप आंचलिक प्रबंधक -चंडीगढ़ श्री सौरभ प्रसाद तथा मुख्य प्रबंधक, पंचकूला क्षेत्र के सभी अधिकारिगण एवं हमारे सम्मानित ग्राहक और मीडियाकर्मी भी मौजूद थे। पंचकूला-हरियाणा के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित शाखा से क्षेत्र के व्यक्तियों, व्यवसायों और उद्यमियों की बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की विशेष भूमिका: ओएसडी वीरेंद्र बढ़ खालसा

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और निर्णायक है। उपरोक्त विचार मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बढ़ खालसा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के साथ संवाद करते हुए प्रकट किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को कुदृढ प्रबोधन, स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रहित जैसे विषयों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे सशक्त ऊर्जा भी हैं, जो किसी भी राष्ट्र को नई दिशा और गति प्रदान कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत जैसे युवा देश में, जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, वहां राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी अनिवार्य हो जाती है। यदि युवा अपनी शक्ति, समय और प्रतिभा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, तो देश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया जा सकता है। वीरेंद्र बढ़ खालसा ने युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज का समय प्रतिस्पर्धा का है और केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता और नवाचार की सोच भी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करें और रोजगार खोजने के बजाय रोजगार सृजन करने वाले बनें। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी शामिल है। युवाओं को चाहिए कि वे समाज में व्याप्त कुरीतियों, नशे, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और एक सकारात्मक बदलाव के वाहक बनें। ओएसडी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं युवाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। युवाओं को चाहिए कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाते हुए देश के विकास में योगदान दें।

युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, कौशल संवर्धन और व्यक्तित्व निर्माण के लिए निरंतर प्रभावी योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय जागरूकता से भी सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आयोजित नेचर कैंप, ट्रैकिंग कार्यक्रम, कौशल विकास शिविर और जागरूकता अभियान युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को नेचर कैंप थापली जैसे प्राकृतिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण करवाने का उद्देश्य उन्हें हरियाणा की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और पर्यावरणीय समृद्धि से परिचित कराना है। इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करते हैं तथा उन्हें प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं।

संरचनात्मक सुरक्षा एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जांच के निर्देश जारी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2019 को सिविल रिट याचिका संख्या 2309/2014 में पारित आदेश के माध्यम से चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को यह निर्देश दिए गए थे कि यह पता लगाने हेतु एक समिति का गठन किया जाए कि भवन आवासीय उपयोग के लिए असुरक्षित है या नहीं। तदनुसार, आदेश संख्या 08 दिनांक 13.12.2019 के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और समिति की रिपोर्ट माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय ने अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को दूर करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश भी दिए। इसके उपरांत, सिविल रिट याचिका संख्या 2309/2014 का निपटारा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2022 के निर्णय के माध्यम से किया गया। न्यायालय ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को निम्नलिखित निर्देश दिए: एक माह के भीतर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटकों जैसे स्तंभ (पिलर्स), भार-वहन करने वाली दीवारें, नींव तथा कैंटिलीवर, जिनमें परिवर्तन या हटाया गया है, को बहाल किया जाए। सभी प्रभावित आवासीय इकाइयों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उक्त बहाली की लागत संबंधित आवंटियों से, उल्लंघन की सीमा के अनुसार, स्वीकृत दरों के अनुसार प्रोराटा आधार पर वसूल की जाए। इन्हें समय-समय पर विभिन्न सार्वजनिक सूचनाओं/नोटिसों के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वे अपने आवासीय इकाइयों के संरचनात्मक पहलुओं की बहाली हेतु आवश्यक कदम उठाएं, जिसमें किए गए अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन शामिल हैं, तथा अपने व्यय पर संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण-पत्र चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को प्रस्तुत करें।

हरियाणा सरकार ने एचआईवी/एड्स नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाए ठोस कदम: 47.16 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, पंचकूला में दूसरी वायरल लोड लैब होगी स्थापित, जीवनसाथी की जांच पहल भी होगी शुरू

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा में एचआईवी/एड्स के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में आज हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (एचएसएसी) की 23वीं कार्यकारी समिति की बैठक हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में बजट प्रावधान, तकनीकी, जांच सेवाओं के विस्तार तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वर्ष 2026झ27 के लिए 47.16 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। समिति ने वर्ष 2026झ27 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 47.16 करोड़ रुपये से अधिक है।

इस बजट में लक्षित हस्तक्षेप और लिंक वर्कर स्कीम के लिए 16.45 करोड़ रुपये, कल्ब्ड/इरूसेवाओं के लिए 10.90 करोड़ रुपये, संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए 6.22 करोड़ रुपये, देखभाल, सहयोग एवं उपचार (अफ्स) के लिए 4.68 करोड़ रुपये, विभिन्न गतिविधियों के लिए 3.75 करोड़ रुपये तथा रक्तसेवाओं के लिए 1.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में दूसरी एचआईवी वायरल लोड लैब को मंजूरी मिल चुकी है, जिसे एक माह के भीतर पंचकूला में शुरू किया जाएगा। वर्तमान में पीजीआईएमएस रोहतक स्थित एकमात्र लैब 17 जिलों को सेवाएं दे रही है, जबकि 5 जिले नई दिल्ली स्थित कल्ब्ड्सर से जुड़े हुए हैं।

पंचकूला में नई लैब के शुरू होने के साथ, ज़िलों को तीन वायरल लोड लैब के बीच पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा – जिससे जांच रिपोर्ट मिलने में लगने वाला समय कम होगा। इसके अतिरिक्त, कैथल, हिसार, पानीपत और फरीदाबाद में चार नई उच्च मशीनें स्थापित की गई हैं, जो जल्द ही चालू हो जाएंगी। इससे निगरानी और देखभाल के लिए राज्य में बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूती मिलेगी। करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं पंचकूला के सिविल अस्पताल में नई उच्च लैब स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत सभी गर्भवती महिलाओं के साथ उनके जीवनसाथियों की भी एचआईवी और सिफलिस की एक साथ जांच करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ठाउउड के संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा में 5,95,880 जांच का लक्ष्य निर्धारित है। इस नई पहल के तहत प्रति वर्ष लगभग 12 लाख संयुक्त जांच की आवश्यकता होगी, जिससे एचआईवी और सिफलिस के मातृ-से-शिशु संक्रमण को लगभग शून्य तक लाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

इसके साथ ही एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित वेब-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करने को मंजूरी दी गई है, जिसके माध्यम से वॉइस मैसेज, एसएमएस अलर्ट और फॉलो-अप रिमाइंडर भेजे जाएंगे। इससे उपचार में निरंतरता बनी रहेगी और मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

बैठक में एचआईवी जांच और उपचार से जुड़े क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। विभाग 95-95-99 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत 95 प्रतिशत संक्रमित व्यक्तियों की पहचान, 95 प्रतिशत को समय पर उपचार से जोड़ना और 99 प्रतिशत मरीजों में वायरल लोड को नियंत्रित करना शामिल है।

इस दिशा में जागरूकता अभियान, जांच सेवाओं का विस्तार, प्रणाली को मजबूत करना तथा नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे न केवल मरीजों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि नए संक्रमणों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। डॉ. सुमिता मिश्रा ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि जागरूकता ही सामाजिक कलंक को खत्म करने और समय पर पहचान सुनिश्चित करने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रमिक–चाहे वह औपचारिक क्षेत्र में हो या गिग वर्कर–तक पहुंच बनाना आवश्यक है।

बैठक में श्रम एवं उद्योग विभाग को सभी बड़े संस्थानों में एचआईवी/एड्स कार्यस्थल नीति लागू करने और उससे गतिविधियों में एचआईवी रोकथाम को शामिल करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने शिक्षा विभाग को सभी सरकारी एवं निजी कॉलेजों में रेड रिबन क्लब स्थापित करने, स्कूलों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम लागू करने के भी निर्देश दिए गया। महिला एवं बाल विकास अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाएं।